RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 08 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 27 नवम्बर 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की देहलीज तक ले जाता है...

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

एसआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। जिसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि, मतदाता सूची का पूरनिरीक्षण का कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। ताकि इस प्रकार विशेष अभियान ना चलाना पड़े। लोकतंत्र की मूल आत्मा निर्वाचन यानी चुनाव है और चुनाव बिना निर्वाचन नामावली के संभव नहीं है। अगर मतदाता सूची ही शुद्ध नहीं होगी तो निर्वाचन शुद्ध कैसे हो सकता है...? इसलिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का हर भारतीय को न केवल समर्थन करना चाहिए वरन चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी को यथा संभव मदद भी करना चाहिए। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कार्य है और राष्ट्रीय कार्य के लिए चुनाव आयोग या सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक आम भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है।

एक घर में 104 वोटर

इस एसआईआर सर्वे में भोपाल से एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया जहां एक परिवार में 104 वोटर है। लेकिन उस परिवार में केवल चार लोग ही निवासरत है। भोपाल की नरेला विधानसभा के बूथ क्रमांक 57 के मकान नंबर एक का यह मामला है। मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग भी इस बात से अब तक अनभिज्ञ थे। यही नहीं एक परिवार के 21 जातियों के लोगों के निवासरत होने की बात सामने आई है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि, इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद भी लोग क्या एसआईआर का विरोध करेंगे...?

बीएलओ के बारे में आयोग का संज्ञान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। और लिखा कि, एसआईआर सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है।

एसआईआर के नाम पर देशभर मे अफरा-तफरी मची है जिसका नतीजा है कि, देशभर में 23 बीएलओ की जान अबतक चली गई जिसका कारण तनाव, हार्ट अटैक व आत्महत्या है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बिहार में तो इन राज्यों से कम समय में एसआईआर हुआ। लेकिन वहां ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई। जबकि बिहार में एसआईआर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में लगभग 450 बीएलओ को निलंबित भी किया गया था। निश्चित रूप से अगर इतनी संख्या में बीएलओ की मौते हुई है तो निष्पक्ष जांच की जाना आवश्यक है।

एक घटना और घटित हो गई जिसमें विदिशा के शासकीय आवास से तीसरी मंजिल से गिरकर एक महिला अधिकारी नायब तहसीलदार कविता कड़ेला की मौत हो जाती है। जिसके बाद इस घटना के पीछे एसआईआर का तनाव बताया जा रहा है। अब ये जांच के बाद ही पता चल सकता है कि, यह घटना हत्या है... आत्महत्या है... या एसआईआर का तनाव है...? बहरहाल एसआईंआर को लेकर आयोग द्वारा अधिकारियों पर इतना दबाव बनाना भी ठीक नहीं है। आयोग फील्ड की हकीकत को समझकर माननीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भी कार्य को पूरा करवा सकता है। क्योंकि अंततः काम तो फील्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा और फील्ड की व्यवहारिक परेशानियां दिल्ली और भोपाल के ऐसी ऑफिस में बैठकर नहीं समझी जा सकती है। निश्चित रूप से एसआईआर अपेक्षाकृत एक श्रम साध्य प्रक्रिया है जो जटिल अवश्य है लेकिन असंभव नहीं है। ऐसे में बीएलओ इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरे तन-मन के साथ पूर्ण करने में जुड़े हैं। कई बीएलओ ने समय पूर्व ही 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है जो अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणादायक है। बीएलओ लोकतंत्र के प्रहरी बनकर मोर्चे पर डटे है। ऐसे में अगर फील्ड में कोई भी व्यावहारिक दिक्कत आ रही है तो उसका यथोचित समाधान भी चुनाव आयोग द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर किया जाना चाहिए। क्योंकि काम का पूरा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना काम का सही व ढंग से पूर्ण किया जाना। एसे में अगर समय की कमी होने पर समयावधि की बढ़ोतरी करना भी सही निर्णय रहेगा।

एसआईआरः 23 बीएलओ की मौत, आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में 23 बीएलओ की मौत के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि, वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को है।

वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि, तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील ने बताया कि, यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से ज्यादा डेटा डिजिटाइज हो चुका है। वकील ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं।

इधर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव है।

ऑनलाइन मनी गेमिंग युवाओं को दे रहा आर्थिक और मानसिक चोट

नई दिल्ली, एजेंसी।

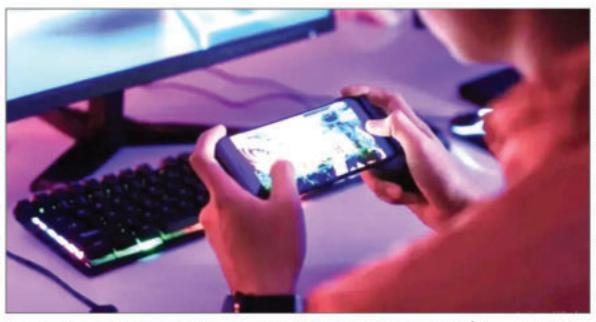

ऑनलाइन मनी गेमिंग के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना सख्त रुख साफ कर दिया है। सरकार ने अदालत में दाखिल विस्तृत हलफनामे में कहा है कि अनियंत्रित ऑनलाइन मनी गेमिंग युवाओं को आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और कर्ज जैसे गंभीर जोखिमों की ओर धकेल रहा है। इसके अलावा, इसकी कड़ी कई मामलों में आतंकवाद के वित्तपोषण, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी से भी जुड़ी पाई गई है। ऐसे में इससे जुड़े नए कानून पर सवाल उठाना अभी जल्दबाजी होगी।

सरकार ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्गों को नशे, कर्ज, मानसिक दबाव और निजी जानकारी के दुरुपयोग जैसे खतरों से बचाना है। सरकार का कहना है कि यह कानून केवल सामाजिक हित के लिए ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हलफनामे में केंद्र ने दावा किया है कि अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का उपयोग बड़े पैमाने पर धन शोधन, कर चोरी और अवैध अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए हो रहा है। कई मामलों में इस उद्योग के जरिए आतंकवाद को वित्तीय सहायता पहुँचाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। सरकार ने कहा कि इस संबंध में मौजूद सबूत अदालत को बंद लिफाफे में सौंपे जाएंगे।

सरकारी जांच के आधार पर हलफनामे में बताया गया कि संदेहास्पद लेन-देन और सीमा पार धन हस्तांतरण की रिपोर्टों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ छोटे द्वीपीय देशों में पंजीकृत पाई गईं, जहाँ वित्तीय निगरानी बेहद कमजोर है। भारतीय उपयोगकर्ताओं से एकत्र की गई धनराशि को देश के बैंकों में प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए खातों से गलत जानकारी देकर विदेश भेजा गया। इस धन का उपयोग कहाँ किया गया, इसकी पड़ताल करना मुश्किल हो जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह भी कहा कि चूँकि यह कानून अभी अधिसूचित नहीं हुआ है, इसलिए इसकी वैधता पर विचार करना समय से पहले होगा। सरकार का कहना है कि कानून लागू होने के बाद ही इसके वास्तविक प्रभाव और परिणामों का आकलन किया जा सकेगा।

जानकारों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अब अगली सुनवाई में सरकार द्वारा प्रस्तुत गोपनीय दस्तावेजों और तर्कों का अध्ययन करेगा। इस बीच, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़े पक्ष भी मामले की कार्यवाही पर करीबी नजर रखे हुए हैं।

कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा फिर गर्माने की तैयारी

मथुरा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को एक बार फिर जनता के बीच लाने की रणनीति तैयार हो रही है। सत्तारूढ़ दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन संत समाज के माध्यम से इसे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का रूप देने की योजना बनाई जा रही है। हाल में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक की विशाल पदयात्रा को इसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

भाजपा और संघ ने वैचारिक रूप से अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े प्रश्नों का समर्थन किया है, परंतु अयोध्या की तरह काशी और मथुरा को कभी आधिकारिक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल के दिनों में स्पष्ट किया था कि संगठन के औपचारिक एजेंडे में केवल अयोध्या था, मथुरा नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे आंदोलन से जुड़ना चाहे तो वह स्वतंत्र है।

सूत्रों के अनुसार अब मथुरा के प्रश्न को न्यायालयी प्रक्रिया के साथ-साथ संत समाज के माध्यम से जनजागरण अभियान का रूप दिया जाएगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक की पदयात्रा से यह संकेत मिला है कि ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण से जुड़े विषयों पर लोगों की भावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। इस यात्रा में बड़ी संख्या में संत, साधु और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। अब इस जनभावना को क्रमबद्ध तरीके से कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के समर्थन में आगे बढ़ाया जा सकता है।

रणनीतिक दृष्टि से इसका एक बड़ा लाभ यह माना जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि का प्रश्न यादव समाज को भी जोड़ सकता है, क्योंकि यह समाज स्वयं को भगवान कृष्ण का वंशज मानता है। इससे समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि उसका मुख्य आधार यादव मतदाता ही है।

इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज क्षेत्र में सक्रियता दिखाई। वे हेलीकॉप्टर से बरसाना पहुंचे और सबसे पहले माताजी गौशाला में गायों की सेवा की। इसके बाद रोप-मार्ग से राधारानी मंदिर पहुँचकर दर्शन किए औरमाथा टेका। वहाँ मौजूद संतों, कार्यकर्ताओं और भक्तों ने पारंपरिक विधि से उनका स्वागत किया।

गडकरी उसके बाद गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक पद्मश्री रमेश बाबा की चल रही भागवत कथा में पहुँचे और उनसे आध्यात्मिक संवाद किया। उन्होंने कहा, बरसाना केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का स्रोत भी है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे देश को दिशा दे सकती है।

26-11 बरसीः गृह मंत्री ने आतंकवाद पर भारत की जीरो सहनशीलता नीति पर दिया जोर

नई दिल्ली, एजेंसी।

मुंबई में 26-11 आतंकी हमलों की आज, बुधवार को 17वीं बरसी है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के प्रति भारत की 'शून्य सहनशीलता' नीति पर विशेष जोर दिया।

ज्ञात हो कि 26 नवंबर 2008 की रात 10 आतंकवादियों का एक समूह समुद्री मार्ग से मुंबई में घुस आया था और 60 घंटे तक लगातार कई स्थानों पर हमले किए थे। इन हमलों में 166 लोग मारे गए तथा अनेक लोग घायल हुए थे। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन भवन, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा तथा लियोपोल्ड कैफे प्रमुख निशाने पर थे। मीडिया सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न सहन करने की नीति स्पष्ट है। पूरा विश्व भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों की सराहना कर रहा है और उसे व्यापक समर्थन दे रहा है। मुंबई हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आतंकवाद किसी एक देश का नहीं, बल्कि समूची मानव जाति का अभिशाप है। अमित शाह ने कहा कि 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायरतापूर्ण हमला किया था। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों का डटकर सामना करते हुए बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ तथा इस हमले में जान गंवाने वाले सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

आज का भारत बड़े फैसले भी ले रहा - पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह निवेश और नवाचार का स्वागत करता है। उन्होंने बताया कि ''उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)'' ने वैश्विक उत्पादकों को ''मेक इन इंडिया'' की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 40 हजार से अधिक अनुपालनों को कम किया है और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ने विभिन्न प्रक्रियाओं को एक ही मंच पर लाकर उद्यमों को बड़ी राहत दी है।

हैदराबाद में ''सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सेवा इंडिया सुविधा के उद्घाटन पर अपने वर्चुअल संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत केवल बड़े सपने नहीं देख रहा, बल्कि बड़े निर्णय लेकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत का ध्यान कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने पर है। उन्होंने कहा कि आज से देश का विमानन क्षेत्र नई उड़ान भरने जा रहा है। यह नई सुविधा भारत को वैश्विक एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल) केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और हाई-टेक व एयरोस्पेस क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र भारत में कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की गई है और व्यापार को आसान बनाया गया है। रक्षा जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले निजी कंपनियों के लिए स्थान नहीं था, आज 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वचालित मार्ग से संभव हो गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से विस्तार के कारण एमआरओ सेवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। देश की विमानन कंपनियों ने 1500 से अधिक विमान का ऑर्डर दिया है। पहले भारत का 85 प्रतिशत एमआरओ कार्य विदेशों में होता था, जिससे समय और धन दोनों की अधिक खपत होती थी और विमान लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। सरकार अब एक बड़े वैश्विक एमआरओ केंद्र के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सफ्रान की प्रशिक्षण प्रणाली और ज्ञान हस्तांतरण, तथा भारतीय संस्थानों के सहयोग से देश में एक ऐसा कार्यबल तैयार होगा जो आने वाले समय में एमआरओ तंत्र को नई गति और दिशा देगा। इससे दक्षिण भारत के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में शिपिंग क्षेत्र से जुड़े एमआरओ ढांचे पर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सफ्रान की टीम से आग्रह किया कि वे भारत में विमान इंजन और पुर्जों के डिजाइन की संभावनाओं को भी तलाशें। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े एमएसएमई नेटवर्क और युवा प्रतिभा के सहकार से यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सफ्रान से कहा कि वे प्रपल्सन डिजाइन और निर्माण में भी भारतीय प्रतिभा का उपयोग करें।

निजी भूमि और रास्ते के पास शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद

ग्रामीणों ने जताया विरोध, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर किया निराकरण

रामूनाथ और परिवार के खिलाफ ग्रामीणों और भूमि स्वामी ने की कार्रवाई की मांग

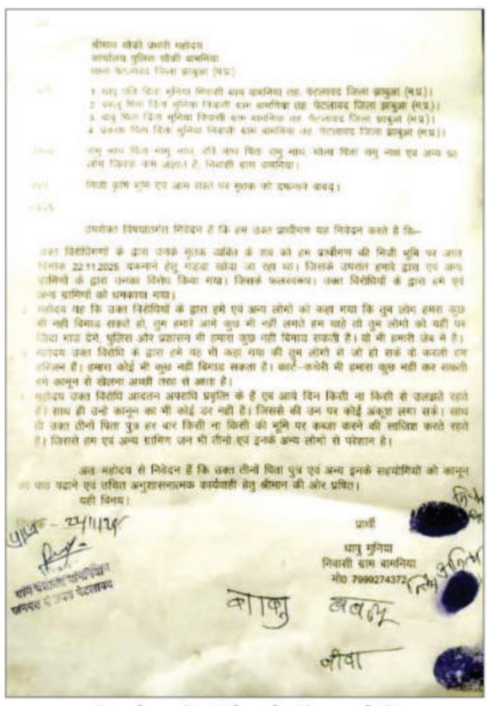

भूमि स्वामी द्वारा पुलिस चौकी पर की गई शिकायत की प्रति।

विवाद के बाद बड़ी संख्या में मौके पर जमा काज़लिया के ग्रामीण और नाथ समाज के लोग।

इस प्रकार निजी खेत में खड़ी फसल पर गड्ढा खोद कर शव दफनाने की कोशिश।

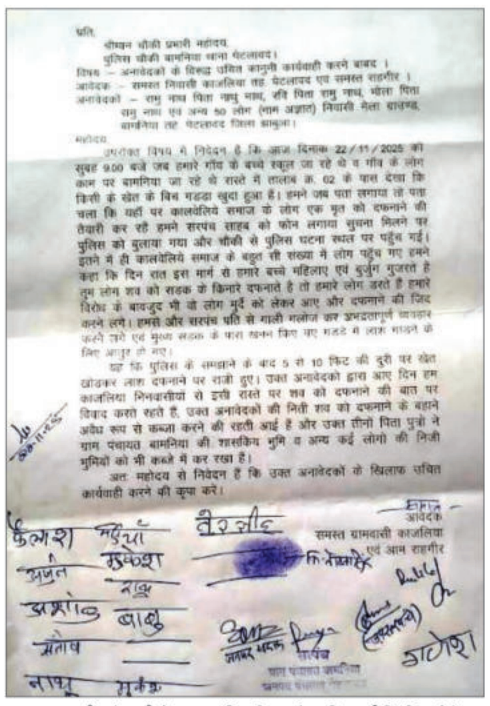

ग्राम काज़लीया के ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज करवाते हुए विवाद की स्थिति बनने के चलते की गई सामुहिक शिकायत।

माही की गूंज, बामनिया/पेटलावद

ग्राम पंचायत बामनिया में अतिक्रमण माफिया रामूनाथ से जुड़ा एक ओर बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया, जहा मृतक के शव को दफनाने को लेकर नाथ समाज और ग्राम पंचायत बामनिया के काजलिया फलिये के ग्रामीण आमने सामने हो गए। शनिवार को नाथ समाज के एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके अंतिम संस्कार लिए नाथ समाज के लोग बामनिया-काजलिया मार्ग पर कचरा डंपिंग ग्राउंड के आगे एक गड्ढा खोद कर शव को दफनाने को कोशिश की, जिस भूमि पर गड्ढा खोदा गया वो निजी बताई जा रही है और वहां गेहूं की फसल लगी हुई थी। जैसे ही खेत में गड्ढा खोदने की जानकारी भूमि स्वामी ओर ग्रामीणों को लगी तो लोग ने विरोध दर्ज करवाते हुए आम रास्ते के किनारे ओर निजी खेत में शव दफन करने का विरोध किया जिसको लेकर बड़े विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, सूचना के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, उप सरपंच सहित पुलिस मौके पहुंची जिसके बाद पुलिस ने मौका स्थिति देख कर शव दफन करने के लिए नाथ समाज को स्थान परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर करने को कहा गया वही नाथ समाज की ओर से विवादित रामूनाथ ओर उसके परिवार के लिए शव को उसी स्थान पर दफनाने लिए अड़े रहे।

दो घंटे से ज्यादा चलती रही बहस, बड़े विवाद की स्थिति बनी

मामले को लेकर दो घंटे से ज्यादा समय तक विवाद चलता रहा। एक और ग्रामीण रास्ते के पास शव दफनाने को लेकर विरोध करते रहे तो वहीं रामूनाथ ओर उसके परिवार के लोग भूमि को समाज का शमशान ओर पूर्व से यही शव दफनाने की बात कह कर शव उसी स्थान पर अड़ा रहा। पुलिस की समझाइश का भी कोई फर्क नहीं पड़ा जिसके बाद पुलिस को दोबारा मौके पर आना पड़ा, दूसरी बार पुलिस के मौके पर आते ही, नाथ समाज के लोग दूसरा स्थान खोज कर शव दफनाने के लिए दूसरा गड्ढा खोदने को तैयार हुए।

फोन पर शिकायत कर धमकाता रहा रामूनाथ, श्मशान के लिए आवंटित नहीं है भूमि

पूरे विवाद के दौरान रामूनाथ फोन पर अलग-अलग अधिकारियों ओर सीएम हेल्प लाइन पर फोन कर मौके पर आने वाले लोगों, ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों ओर पुलिस को लेकर शिकायत करते हुए हर किसी पर आरोप लगाने का काम करता रहा, वहीं उसके परिवार के लोग हर बार की तरह वीडियो बनाने का काम करते रहे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते से रोज हमारे गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते है और श्मशान नहीं होने के बाद भी यहां मनमाने तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा यहां गुजरने वाले बच्चों को आने जाने में डर लगता है वही हमारी खेती भी यही ओर रात बेरात खेत पर रहना पड़ता है जिससे यहां डर का माहौल रहता है। जनपद सदस्य सोहन डामर से जब चर्चा की तो उन्होंने ने बताया कि यहां किसी प्रकार की भूमि शमशान के लिए आवंटित नहीं है। ग्रामीणों को परेशानी हैं तो इसकी विधिवत शिकायत कर यहां अंतिम संस्कार बंद करवाया जाएगा।

भूमि स्वामी ओर ग्रामीणों ने अलग-अलग आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग

भूमि स्वामी धापू मुनिया, बाबू मुनिया, बबलू मुनिया और प्रकाश मुनिया को ओर से पुलिस चौकी बामनिया में आवेदन देकर निजी भूमि को जबरन श्मशान में बदल कर कब्जा करने ओर आए दिन विवाद करने को लेकर रामूनाथ, भोलानाथ, रविनाथ के विरुद्ध निजी भूमि पर कब्जा करने ओर रास्ते के पास शव दफनाने की शिकायत दर्ज करवाई। भूमि स्वामी धापू मुनिया ने बताया कि इनके द्वारा कोई भी नाथ समाज के व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव दफनाने का काम हमारी भूमि के आसपास किया जाता है और विरोध करने पर जिंदा इसी जमीन में गाड़ने की धमकी दी जाती है, धीरे धीरे ये लोग हमारी निजी जमीन को शमशान बना कर कब्जा करने को कोशिश कर रहे है ओर इस प्रकार डरा धमका कर इन्होंने कई लोगो की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं ग्राम काजलिया के ग्रामीणों द्वारा एक सामूहिक आवेदन पुलिस चौकी पर देते हुए रामू नाथ सहित समाज के अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए, रामू नाथ व अन्य लोगों कर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दे कि रामू नाथ द्वारा लगातार लोगों की निजी ओर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले सामने आए है, ग्राम नारेला ओर बामनिया में निजी भूमि पर कब्जा करने ओर भूमि स्वामी की खेत की खड़ी फसल काटने, धमकाने, विवाद झगड़ा करने के मामले खवासा चौकी ओर बामनिया चौकी में दर्ज हो चुके है। रामूनाथ सहित परिवार के अन्य सदस्य थाने से जमानत पर इसके बाद भी लगातार विवाद कर आम लोगों को परेशान कर रहे है। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों में जांच कर कार्यवाही की बात की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा हैं कि अगर नाथ समाज को यहां शव दफनाने से नहीं रोका तो इसकी शिकायत जिला कलेक्टर ओर एसपी साहब को करेंगे क्योंकि उक्त भूमि पर किसी भी समाज के श्मशान के लिए भूमि आबंटित नहीं है।

जल जीवन -जल मिशन में बनी पानी की टंकी में ग्रामीणों को नही मिल रहा है पानी

मामला : थांदला जनपद की ग्राम पंचायत चापानेर का

माही की गूंज, खवासा।

एक तरफ जहां केंद्र सरकार जल जीवन जल मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के दावे के साथ बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो की गई लेकिन धरातल पर किस तरह से योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया यह किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचलों में योजनाओं के नाम पर आने वाली राशि में बंदर बाट हो ही जाती है। तो मॉनेटिंग करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के सानिध्य में ठेकेदार खुलकर भ्रष्टाचार करके अपनी जेब गर्म करते हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे अच्छा खासा कमीशन लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। तो वही पंचायत भी बड़े स्तर पर ठेकेदार से तालमेल बिठाकर इस अधूरी योजनाओं को हस्तांतरित करके अपने अधीनस्थ कर लेती है। उसके बाद ग्रामीण अंचलों में लोगों को समय पर पानी ही नहीं मिल पाता है। यह किसी से छुपा भी नहीं है। आज कई ग्राम पंचायत में जल जीवन जल मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकियां में पानी ही नहीं उपलब्ध हो रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों को वापस उसी स्थिति में पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माही की गूंज पूर्व में भी कहीं ग्राम पंचायत की प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है, जो आज भी उसी तरह से टंकियां का निर्माण वीरान पड़ा हुआ है। वही ग्रामीण जो पूर्व में पानी ला रहे थे उसी तरह से गांव की महिलाएं आज भी कुए व बावड़ी से पानी ला रही है। लेकिन जल जीवन जल मिशन में बनाई गई पानी की टंकियां का किस तरह से निर्माण किया गया है यह किसी से छुपा भी नहीं है। और इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है यह भी सत्य है। माही की गूंज को मिली प्राप्त जानकारीनुसार कुछ ऐसा ही मामला थांदला जनपद की ग्राम पंचायत चापानेर में सामने आया। जहां चापानेर ग्राम में जल जीवन जल मिशन के तहत पानी की टंकी स्टील ग्रुप आफ कंपनी रतलाम द्वारा निर्माण किया गया था। बताते हैं, ठेका गुजरात के सूरत के किसी व्यक्ति का था। तथा जहां पाइप व नल लगाए गए उसमें अनियमिता कंपनी द्वारा की गई थी वही नियमों के मुताबिक जिस ठेकेदार के माध्यम से काम किया गया है। उसे 2 साल तक ठेकेदार को गांव में पानी सप्लाई के साथ पूरी तरह से सुचारू रूप से पाइपलाइन बना कर देने का जिम्मा भी इस ठेकेदार के माध्यम से होता है। लेकिन यहां ठेकेदार ने जल्दी कमीशन के चक्कर में वह ग्राम पंचायत ने मिलकर योजना अपने अधीनस्थ कर ली जिसके कारण आज यह योजना धरातल पर कारगर साबित नहीं हो रही है, बताते हैं। कि ठेकेदार ने टंकी वह पानी टेसिंटग के बाद योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। चापानेर ग्राम पंचायत में एक माह से पानी नलों में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों से जुझना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अपने ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराने में कारगर साबित नहीं हो पा रही है। जिसके कारण कहीं ना कहीं लगता है। कि ठेकेदार वह ग्राम पंचायत में कमीशन खोरी के चक्कर में आधी अधूरी योजना हस्तांतरित कर ली जिसके कारण आज यह योजना ग्राम पंचायत से सही से संचालन भी नहीं हो पा रही है। अंदर की जानकारी रखने वाले बताते हैं। कि यहां भाजपा समर्पित सरपंच प्रतिनिधि है। और उनके द्वारा ही ग्राम में नल सप्लाई के लिए ग्रामीणों को रखा गया था लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने गांव में नल देने का कार्य बंद कर दिया गया तो वही बताते हैं, कि ग्राम पंचायत में कोई कर वसूली नहीं होती है। जिसके कारण लड़कों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था। उन्होंने पंचायत में काम करना बंद कर दिया इसी वजह से ग्राम में नल नहीं दिए जा रहे हैं। यह पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि योजना में भ्रष्टाचार किया गया है। जिस इस्टीमेन्ट के हिसाब से गांव में पाइपलाइन डालना थी उसके हिसाब से ठेकेदार ने काम ही नहीं किया जब भी आए सरपंच से मिले और मामला रफा-दफा कर लिया प्रदेश व केंद्र सरकार ग्रामीण के लिए योजना आती है, तो ग्राम में हर स्तर पर उसका अच्छी तरह से संचालन होना चाहिए लेकिन यहां तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पानी की टंकी में ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण यहां के ग्रामीण व युवकों को वह बुजुर्ग महिलाओं को पानी के लिए परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है, कि यहां जल्द से जल्द ग्राम पंचायत पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई और जिस योजना के माध्यम से टंकी का निर्माण किया गया उसमें भी कोई अनियमिता है। तो इसकी भी जांच की जाए और ग्राम पंचायत में अगर अधूरी योजना हस्तांतरित किए थे इसमें भी वरिष्ठ अधिकारी जांच करें यह मांग माही की गूंज के माध्यम से ग्रामीणों ने की है।

वही मामले में सरपंच प्रतिनिधि कान्हा मुनिया से चर्चा की उन्होंने कहा कि ग्राम में पानी सप्लाई एक माह से बंद है, यह बात सही है। जिन लड़कों को कार्य के लिए रखा गया था उनके द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। क्योंकि समय पर उनका वेतन नहीं मिल रहा था गांव में जहां भी नल लगे हैं। वहां गांव के लोग पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। जिसके कारण समय पर लड़कों को वेतन नहीं मिल रहा है। और वह अब काम पर चले गए हैं। ग्राम पंचायत जल्द ही कोई व्यवस्था करके पानी ग्राम में उपलब्ध करवाई। यह कहकर अपने कार्य से इति श्री कर ली।

गूंज असरः जिम्मेदारो की खुली नींद ,हाई स्कूल के बच्चों को मिला विशेषज्ञ विज्ञान शिक्षक

माही की गूंज, पेटलावद।

राज्यपाल के सामने जिला प्रशासन को लजवाने वाले संकूल प्राचार्य की हठधर्मिता

सैकड़ों बच्चों की जीव विज्ञान विषय की शिक्षा रामभरोसे, एक संकूल में प्राचार्य ने अतिथि भर्ती में बनाए अलग-अलग नियम

अतिथि भर्ती में लापरवाही और करडावद स्कूल में विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी को लेकर प्रमुखता से प्रकाशित खबरे।

अतिथि भर्ती में सरकारी नियमो की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी और प्राचार्य

हमारे द्वारा लगातार पेटलावद ब्लॉक की शैक्षणिक व्यवस्था सुधार हेतु खबरें प्रकाशित कर क्षेत्र के बच्चों व पालकों के हित में समाचार प्रकाशित किए जाते रहे हैं उसी क्रम में हमारे द्वारा करड़ावद हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षा से वंचित छात्रों के लिए शीर्षक ÷ राज्यपाल के सामने जिला प्रशासन को लज्वाने वाले प्राचार्य की हठधर्मिता÷ से समाचार प्रकाशित किए गए थे, उसका असर हुआ और वहां के बच्चों को विज्ञान विषय के विशेषज्ञ अतिथि शिक्षक की पूर्ति की गई। जिसमें पात्र अतिथि की भर्ती कर दी गई है दिनांक 21/11/2021 को ही खण्ड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र ओझा द्वारा प्रभारी प्राचार्य को विज्ञान विषय पर प्राप्त अतिथि शिक्षक आवेदन में पात्र महिमा चौधरी एमएससी बीएड योग्यताधारी व एमपी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी से कार्य लेने के निर्देश दिए गए उसी के पालन में दिनांक 22/11/2024 को ही संकुल प्राचार्य ने महिमा चौधरी को पदभार दे दिया गया स ज्ञात रहे की हमारे द्वारा संकुल प्राचार्य की हठधर्मिता से सैकड़ों बच्चों की जीव विज्ञान विषय की शिक्षा रामभरोसे होने पर शीर्षक ÷अतिथि भर्ती में नियमो की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी ओर प्राचार्य ÷ से प्रकाशित समाचार से प्रशासन हरकत में आया स वहीं नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी द्वारा लगातार जनसुनवाई में पहुंची और अतिथि भर्ती गड़बड़ी की जांच और खुद को नियुक्ति देने की मांग की गई थी।

कई शिकायते लम्बित

पेटलावद विकास खंड में हुई अतिथि भर्ती की लेकर लगातार शिकायते सामने आ चुकी है तो कई मामलो में शिकायत कलेक्टर ओर सीएम हेल्प लाइन पर अभी भी लंबित है। पूरे विकास खंड में सबसे ज्यादा चर्चा अतिथि भर्ती को लेकर बनाए गए नियमो की हो रही है जहा अलग-अलग संकुल में प्राचार्या ने अपने नियम बना कर भर्ती की है। कुछ स्थानों पर सीधे भर्ती और कुछ स्थानों पर बिना विज्ञप्ति जारी किए बिना भर्ती के मामले उजागर हुए है। शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर अपने निजी फायदे के लिए बच्चों के भविष्य दाव पर लगाने वाले की कार गुज़ारियों गूंज के माध्यम से उजागर करते रहेंगे।

बौखलाहट : गूंज का असर ऐसा कि पत्रकार को जान से मारने तक हो गया उतारू

आदिवासियों से ठगी करने वाला, आदिवासियों का सहयोग क्यों करते हो कहकर रवि टाक ने किया धमकाने का प्रयास

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

जनहितैषी व निष्पक्ष पत्रकारिता काटो का ताज है यह हम भलीभांति जानते हैं। तथा माही की गूंज की निष्पक्ष कलम के साथ हम सहजता से इस काटो के ताज को पहन कर हमारी पत्रकारिता की कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण कर रहे हैं।

वैसे तो माही की गूंज एक साप्ताहिक अखबार है इसलिए जनहितेषी मुद्दे को हम सप्ताह में एक बार गुरुवार को प्रकाशित करते हैं। वह भी किसी दैनिक अखबार की तुलना में कमतर नहीं है। तथ्यात्मक प्रकाशित समाचारों की चर्चाएं कम नहीं होती है और देखते ही देखते सप्ताह गुजर कर पुनः गुरुवार आ जाता है। और पुराने समाचारों के साथ नए समाचारों की चर्चा आम जनता में विश्वास का प्रतीक बनी रहती है। यही हमारे पिछले सात सालों की माही की गूंज की पूरी टीम की सफलता है और हम पाठकों के विश्वास पर खरे उतरते हैं उसकी हमें खुशी भी है। सम्बधिन्तो के प्रति प्रकाशित समाचारों के बाद कई ऐसे वाक्ये आते हैं जिसमें प्रशासन भी अपनी बौखलाहट का परिचय देती हैं।

तो कही समाचार प्रकाशन के बाद माफिया व भ्रष्टाचारी सार्वजनिक चर्चाओं में अपनी गोंवक्ति यही करते हैं कि, समाचार प्रकाशन से क्या हो जाता है। लेकिन तंत्र से तालमेल के साथ मामले को निपटाए जाते हैं जो बातें किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि माही की गूंज में समाचार छपा है तो उसका कहीं न कहीं असर जरूर होता है। एक कर्मनिष्ठ, निष्पक्ष पत्रकार की कलम की सफलता तब सामने आती है जब सामने वाले की बौखलाहट उसके आतंक के रूप में सार्वजनिक होती है। जिससे सार्वजनिक रूप से यह प्रतीत होता है कि, अखबार में छपा समाचार पूर्णतः तथ्यात्मक तो है ही पर उस समाचार का असर अनैतिक या गलत कार्य करने वालों पर उसका इतना असर हुआ है कि वह सिर्फ अपनी झूठी शान व नाक बचाने का प्रयास करते हुए अपने आतंक का परिचय देते है। और कई बार पत्रकारों पर जानलेवा हमले तक कर देते हैं और कई ऐसे देश में मामले भी हुए हैं जिसमें पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिए।

लेकिन जब-जब भी पत्रकारों पर ऐसे हमले होते हैं पत्रकारों की कलम की धार और अधिक तीव्र हो जाती है। क्योंकि कलम की धार तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। मुंशी प्रेमचंद का एक वाक्य कलम का सिपाही कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी कलम को सामाजिक न्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए एक हथियार के रूप में कलम का इस्तेमाल किया था। हमारी कलम भी मुंशी प्रेमचंद के आदर्श पर चलते हुए यशवंत घोड़ावत की कलम की तर्ज पर सामाजिक न्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष के रूप में कलम के सिपाही होकर अपना निर्वाह कर रहे हैं।

ऐसे में चाहे कोई भी माफिया, लोगों से ठगी करने वाले व्यापारी या असामाजिक तत्व हम पर हमले करके हमारी कलम को रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वह प्रयास असफल ही रहेंगे क्योंकि यह कलम न कभी रुकी है और न कभी रुकेगी।

दो राज्य व तीन जिलो में मनमानी करता व्यापारी समाचार से ऐसा बौखलाया की मानो उसके पैरो तले जमीन निकल गई

जो व्यक्ति यह कहते हैं कि, समाचार का असर नहीं होता है लेकिन तथ्यात्मक लिखे समाचारों का कितना बड़ा असर होता है यह एक उदाहरण के रूप में एक बार और सामने आया है।

24 जुलाई के अंक में माही की गूंज में ''एमपी में खाद नहीं मिल रहा लेकिन समीपस्थ बड़ी सरवा (राज.) से व्यापारी धड़ल्ले से 430 में खाद की बोरी एमपी के किसानों को दे रहे हैं'' के शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें उल्लेख था कि, झाबुआ जिले में जहां किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद दिए जाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन असल में यहां खाद नहीं मिलने के चलते खवासा क्षेत्र के किसान समीपस्थ राजस्थान से 266 रुपए में शासन की ओर से दिया जाने वाला खाद 430 रुपए में मजबूरी में ला रहे हैं।

वहीं बड़ी सरवा के एक व्यापारी रवि टाक ने हमारे स्थानीय प्रतिनिधि सुनील सोलंकी से हुई चर्चा में बताया था कि, वह रतलाम (मध्य प्रदेश) जिले से खाद 350 रुपए में लाता है और यहां 430 रुपए में वो खाद किसानों को बेचता है। तथा व्यापारी स्वयं ने खाद बेचने का लाइसेंस उसके पास नहीं है स्वीकार किया था। व्यापारी की कही बात के साथ प्रकाशित समाचार के बाद रवि टाक ऐसा बौखलाया कि, उस समय की टेलिफोनिंग चर्चा में धमकी देने का प्रयास किया। और अन्य व्यक्तियों के सहारे हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को फोन करवाकर गाली-गलौज कर धमकाने का प्रयास किया। लेकिन हमारी कलम इन फिजूल धमकियों से नहीं डरी और आदिवासी किसानों के साथ ठगी करने वाला व मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से ही बिना बिल का यूरिया खाद लाकर सीमावर्ती बड़ी सरवा (राज.) स्थित अपनी दुकान पर खाद लाकर झाबुआ जिले के किसानों को शासन के अधिकृत भाव से अधिक रुपया लेकर ठगी करने वाले व्यापारी रवि टाक की बौखलाहट और बढ़ती गई।

वहीं दुसरा समाचार सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी एवं लाइव लोकेशन के साथ मिले फोटो जिसमें बड़ी सरवा (राज.) से व्यापारी ने अपनी दुकान से सोयाबीन लोड किया और यहां चार सौ बिसी करते हुए व्यापारी ने अपने पैतृक निवास स्थान विनायक ट्रेडर्स अमरपुरा (बाजना) म.प्र. से सोयाबीन भरा बताकर सैलाना मंडी की अनुज्ञा कटवाकर बामनिया अशोक अग्रवाल की कॉटन इंडस्ट्रीज में सोयाबीन पहुंचा के उल्लेख के साथ समाचार प्रकाशित किया था।

एमपी मे खाद नही मिल रहा लेकिन समीपस्थ बड़ीसरवा (राज.) से व्यापारी धड़ल्ले से 430 मे खाद की बोरी एमपी के किसानो को दे रहे

24 जुलाई 2025 के अंक में प्रकाशित समाचार।

व्यापारी व मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत से शासन के पैसों की हो रही बर्बादी

बिना सेल टैक्स व बिना अनुज्ञा के निकल रहे अनाज से भरे वाहन

माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोलंकी

क 8- 30 अक्टुम्बर 2025 के अंक में प्रकाशित समाचार जिसमे बोखलाए व्यापारी का नाम नही पर रवि टाक कहता है मैरे थे सोयाबिन जिसे बडी सरवा (राज.) से किये थे लोड।

स्थानीय प्रतिनिधि के नाम के साथ उक्त प्रकाशित समाचार 30 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था। लेकिन उक्त समाचार में कहीं से कहीं तक किसी व्यापारी का नाम उल्लेख नहीं था। उसके बावजूद भी स्वयं रवि टाक ने अन्य लोगों के माध्यम से फोन लगवाकर इस बात की पुष्टि की कि, यह सोयाबीन भी रवि टाक का ही था और अपनी बौखलाहट कई लोगों के सामने दर्शाता था। मध्य प्रदेश व राजस्थान दो राज्य व इन दो राज्य के बांसवाड़ा, रतलाम व झाबुआ जिले में अपनी चार सौ बिसी रूपी करतूत बताने वाले व्यापारी की वास्तविक करतूत माही की गूंज में प्रकाशित होने पर ऐसा बौखलाया कि, एक सामाजिक आयोजन में विघ्न डाल जान से मारने तक की धमकी व प्रयास अपने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर किया गया।

बता दे कि, बड़ी सरवा (राज.) निवासी के लड़के की शादी समारोह 24 व 25 नवंबर को था। वहीं उक्त बौखलाया व्यापारी भी उक्त शादी में आमंत्रित था। 24 नवंबर को उक्त व्यापारी शादी समारोह उदय मैरिज गार्डन पेटलावद परिसर के अंदर ही समारोह के दौरान माही की गूंज संपादक से संपर्क कर अपना नाम रवि टाक बताया। और कहने लगा कि, हम भी कलाल है और जहां जिस व्यक्ति के पीछे कलाल लग जाता है उसके समाचार आपको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। आपने खाद का समाचार व बड़ी सरवा (राज.) में मेरी दुकान से सोयाबीन भरकर बामनिया गया उसका समाचार भी आपने छाप कर अच्छा नहीं किया और धमकाने लगा। साथ ही बौखलाया रवि टाक प्रत्यक्ष अन्य व्यक्तियों के समक्ष संपादक को कहने लगा कि, तुम आदिवासियों का सहयोग क्यों करते हो! तुम्हें कलालो का सहयोग करना चाहिए! जब संपादक ने बौखलाए व्यापारी को समझाते हुए कहा कि, हम लोग किसी सामाजिक आयोजन में आए हैं यहां हम किसी प्रकार का विघ्न खड़ा नहीं करें। समाचार को लेकर कोई समस्या या नाराजगी है तो हम अपने घर पर भी बैठकर बात कर सकते हैं।

रही बात आदिवासी समाज को सहयोग करने की तो हमारी कलम हर पीड़ित के पक्ष में चलती है, किसी जातिवाद के आधार पर नहीं चलती। अगर कहीं कोई गलत है चाहे वह सगा भाई भी हो तो हमारी निष्पक्ष कलम का हम निर्वहन करते हैं। रही बात झाबुआ, बांसवाड़ा जिला या सैलाना तहसील यह आदिवासी बाहुल क्षेत्र ही है और यहां हर व्यापारी चाहे आप हो या हम इन आदिवासी समाज के भाइयों से ही मिली कमाई के साथ हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं कहा।

उक्त संपादक की बात बोखलाए व्यापारी को और हजम नहीं हुई और आदिवासी समाज के संबंध में अनर्गल बात कर टाक कलाल को सहयोग करने की बात पर जोर देते हुए धमकाने लगा। लेकिन वहां उपस्थित कुछ लोगों ने बोखलाए रवि टाक को अलग ले गए और मामला शांत किया।

समाचार से बौखलाया रवि टाक यही शांत नहीं हुआ दूसरे दिन 25 नवंबर को माही की गूंज का स्थानीय प्रतिनिधि सुनील सोलंकी भी उक्त शादी समारोह में आमंत्रित होकर परिवार के साथ शादी समारोह में आया था। रवि टाक हमारे प्रतिनिधि को शादी समारोह में देखते ही समाजजनों के बीच अपनी बौखलाहट सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए धमकाने लगा। और कहने लगा कि, तुमने राजस्थान का समाचार लिखा है हम तुझे और तेरे संपादक को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने वहां पर भी समझाइस दी और मामला खत्म किया।

संपादक व प्रतिनिधि किसी भी स्थिति में उक्त शादी समारोह में विघ्न न हो की मनसा रखे हुए थे। तो वही बौखलाया टाक बंधु की मनसा विपरीत होकर शादी समारोह में विघ्न डालने की ही रही। और जैसे ही शादी समारोह अटेंड कर संपादक एवं प्रतिनिधि एवं अन्य समाज के एक दो लोग परिवार सहित मैरिज गार्डन से बाहर निकलकर वाहन पार्किंग में जा रहे थे कि, बौखलाया रवि टाक अपने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आया और हमारे प्रतिनिधि को टारगेट में लेने का प्रयास कर हमला करने का प्रयास किया। बीच बचाव में संपादक एवं अन्य लोग बचाव पक्ष में आए लेकिन रवि टाक व साथ में आए बिना आमंत्रित शादी समारोह में असामाजिक तत्वों ने जमकर हमला कर दिया। जिसमें संपादक को चोट लगी व जान से मारने की धमकी देकर अन्य लोगों को आते देख अपने असामाजिक तत्वों के साथ रवि टाक फरार हो गया।

उक्त घटना के बाद शादी समारोह में यही चर्चा चलने लगी कि, बौखलाया रवि टाक ने चवन्नी छाप हरकत कर शादी समारोह में विघ्न डालने का प्रयास किया। अगर समाचार को लेकर कोई दिक्कत थी तो सीधे पत्रकार के घर बात करने जाना था न कि इस तरह की घटिया हरकत करना थी। और यह भी लोगों द्वारा कहा गया कि, ऐसी घटिया हरकत कोई चवन्नी छाप या घटिया व्यक्ति ही कर सकता है!

संविधान मूल्यों के संरक्षण का लिया संकल्प

माही की गूंज ,पेटलावद।

संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को अंबेडकर बस्ती, पेटलावद में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित जनों ने एक-दूसरे को संविधान दिवस की शुभकामनाएँ दीं। संविधान दिवस अमर रहे तथा ÷जय भीम÷ के उदघोष के साथ बाबा साहेब के योगदान का स्मरण किया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक समरसता और संविधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। वक्ताओं ने बताया कि, बाबा साहेब के विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं और नागरिकों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित करते है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष, सीएमओ, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगदीश जाटव, मुकेश सिसोदिया, पार्षद ममता गुजराती, समाजसेवी भेरूलाल पड़ियार, नगर परिषद के समस्त कर्मचारी वर्ग एवं वार्ड की महिलाएँ , कॉलेज के युवा वर्ग आदि उपस्थित थे।

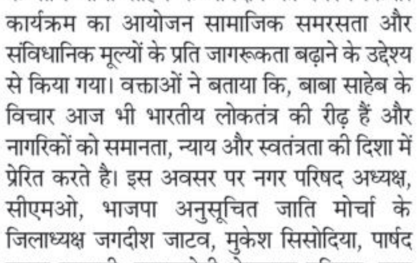

12 करोड़ की धनवर्षा का झांसा देकर 3 लाख की ठगी

माही की गूंज, खरगोन। 12 करोड़ रुपए की धनवर्षा कराने का लालच देकर एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इंदौर क्षेत्र के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हारखेड़ा की है। कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक रामजीलाल डुडवे के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ित घनश्याम चौहान के घर पूजा कराने का बहाना बनाया। उन्होंने एक मटके में 3 लाख रुपए रखने को कहा और दावा किया कि पूजा के बाद इससे 12 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। मंगलवार रात घनश्याम से मटके में रुपए रखवाए गए। इसके बाद आरोपियों ने श्मशान भूमि में नींबू काटकर विशेष पूजा करने के लिए कहा। पूजा पूरी होने के बाद उन्होंने धनवर्षा होने का दावा किया। घनश्याम को तीसरी बार नींबू काटकर 51 बार भैरवजी का नाम लेकर लौटने के लिए कहा गया। जब वह वापस आए, तब तक आरोपी रुपए लेकर फरार हो चुके थे।

रजिस्ट्री का मामला बिगड़ा तो अब जबरन कब्जे का प्रयास

नहीं हो रहा आदेश का पालन, पुलिस अधीक्षक से विधवा महिला ने लगाई गुहार

माही की गूंज, पेटलावद/झाबुआ।

कुछ माह पूर्व पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायत बरवेट में शासकीय भूमि के पट्टे की रजिस्ट्री का मामला उजागर हुआ था। जिसमें विक्रेता ने शासकीय पट्टे की भूमि को बेच कर ग्राम पंचायत के प्रमाण के आधार पर रजिस्ट्री करवा दी थी। जबकि ग्राम पंचायत पूर्व में जारी पट्टे में लिख चुकी है कि, भूमि शासकीय होने से विक्रय नहीं हो सकती। मामले की शिकायत के बाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 25 जुलाई 2025 को पारित आदेश में शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए ग्राम पंचायत में रजिस्ट्री के माध्यम से होने वाले नामांतरण पर रोक लगा दी। तथा भूमि को शासकीय पट्टे की भूमि पाई जाने की पुष्टि कर इसके क्रय-विक्रय नहीं होने का निर्णय दिया था।

पीड़ित विधवा महिला मोनाबाई पति विक्रमसिंह राठौर को उम्मीद थी कि, उसे न्याय मिलेगा लेकिन सरकारी आदेश केवल कागजों में सिमट कर रह गए ओर जिन लोगो ने सरकारी जमीन पर बना कच्चा मकान का एक भाग खरीदा था। उस पर कब्जा करने के लिए तोड़फोड़ कर मकान को नुकसान पहुंचाने ओर प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित मोनाबाई राठौर ने विपक्षियों द्वारा जबरन मकान पर कब्जा करने की कोशिश व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद के द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ शिकायत दर्ज की। लेकिन स्थानीय पुलिस ओर प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पाया। जिसके चलते मोनाबाई राठौर ने मामले में न्याय की गुहार जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंच कर एसपी को आवेदन पेश कर कार्रवाई की मांग की।

इस प्रकार से तोड़फोड़ को लेकर दर्ज करवाई शिकायत।

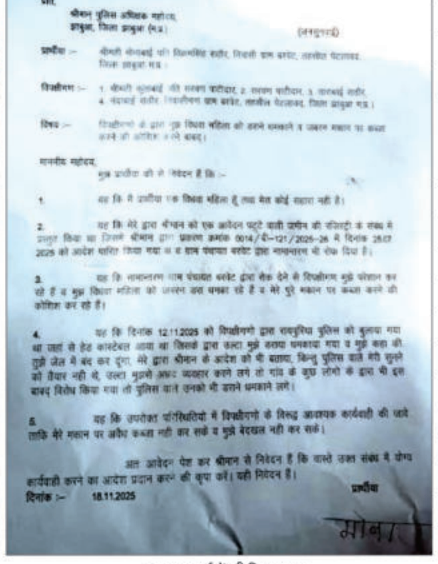
दिनांक :- 18.11.2025

जनसुनवाई में की शिकायत।

जबरन मकान पर कब्जा करने का प्रयास

शिकायत में मोनाबाई राठौर ने बताया कि, राजस्व न्यायालय पेटलावद में शासकीय पट्टे की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने की शिकायत की थी। जो कि जांच के बाद सही पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत में रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण पर रोक लगाई गई थी। विपक्षी कुंताबाई, सरवन ,ताराबाई राठौर,नंदबाई राठौर पर अब जबरन मकान पर कब्जा जमाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक झाबुआ को गई। शिकायत कर्ता मोनाबाई ने बताया कि, न्यायालय से आदेश के बाद भी मेरे पूरे मकान को कब्जा करने के उद्देश्य से मकान में तोड़फोड़ की जा रही हैं जिसकी शिकायत थाना रायपुरिया में की। लेकिन पुलिस द्वारा मुझे डराया धमकाया गया। गांव के जो लोग मेरा सहयोग करते है उनको भी पुलिस धमका कर विपक्षियों के पक्ष में कार्य कर रही है।

रजिस्ट्री से नहीं जमा मामला तो अब कब्जा

शासकीय पट्टे की भूमि को जांच में दो भागों में हक अधिकार पाया गया जिसमे से एक भाग की रजिस्ट्री करवा दी गई जो कि अनुविभागीय न्यायालय में मान्य नहीं हुई। जिस भाग की रजिस्ट्री हुई उसे क्रेता ओर विक्रेता अब बिके हुए भाग को कब्जे के आधार पर क्रेता को कब्जा देने की कोशिश कर रहे है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि, मकान में तोड़ फोड़ कर निर्माण किया जा रहा है और कब्जा क्रेता को जबरन देने की कोशिश की जा रही हैं।

पीड़ित महिला ने बताया कि, मेरे हक में कुछ भाग ही आया है और मेरे स्व. जेठ के तीन बच्चे हैं जो उनके नाना के पास रहते है। भविष्य में हक लेने के लिए आए तो मेरे हक में ही हक मांगेगे जिससे मेरे पास कुछ नहीं बचेगा।

सरकारी भूमि खरीद फरोख्त करने पर कोई कार्रवाई नहीं

मामले की जांच में ये उजागर हुआ कि, सरकारी पट्टे की भूमि की खरीद फरोख्त की गई ओर रजिस्ट्री भी करवाई गई। जो कि गंभीर मामला है और इस तरह से कई ग्राम पंचायतो में ये खेल चल रहा है। मामला उजागर होने के बाद इस प्रकार से शासकीय संपत्ति को बेचने ओर खरीदने के मामले में कार्रवाई होना थी जो कि नहीं की है जिससे विवाद गहराता जा रहा है।

संपादकीय

शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि एक सुधार

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। निश्चित ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए।

दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह 'ऑपरेशन पवन' की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है। चूंकि ऑपरेशन पवन में शहीद हुए कई सैनिकों का अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया विदेशी धरती पर पूरी हुई थी, इसलिए उनके परिजन शहीद सैनिकों के अवशेषों को वापस भारत लाने की नीति को सुव्यवस्थित करने की मांग करते रहे हैं। वे एक ऐसे आयोग के गठन की भी मांग करते रहे हैं जो शहीद सैनिकों के पार्थिव अवशेष को वापस भारत लाने की नीति को तार्किक बना सके। उनकी मांग रही है कि उन अवशेषों को भारत लाकर आईपीकेएफ का एक स्मारक बनाकर, उसमें सम्मान के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, किसी भी देश के वीर शहीदों के स्मारक सामूहिक स्मृति के प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए बलिदान के लिये एक सम्मान और स्मरण स्थल के रूप में चिरस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं। निर्विवाद रूप से इस बहुप्रतीक्षित मांग को हकीकत में बदलने के लिये चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को कम करके आंकने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यदि हम वीर सैनिकों के बलिदान को समुचित सम्मान देते हैं तो इससे तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। इस दिशा में अविलंब सार्थक पहल किया जाना वक्त की जरूरत ही है।

हरफनमौला धर्मेंद्र जो किसी पहचान में नहीं बंधे

हेमन्त पाल

सिनेमा के हर अभिनेता को लंबे अरसे तक याद करने की वजह होती है। फिल्म इतिहास में अमिताभ बच्चन को यंग एंग्रीमैन के रूप में जाना जाता है, ऋषि कपूर की पहचान डांसिंग हीरो की थी, तो राजकुमार की पहचान उनके अलग ही तेवर वाले अंदाज के लिए रही। लेकिन, धर्मेंद्र जैसे अभिनेता के साथ ऐसी कोई पहचान नहीं जुड़ी। 'शोले' का वीरू मस्तमौला था तो 'सत्यवान' में उनका किरदार ईमानदार, नैतिक और संघर्षरत व्यक्ति का था। बंदिनी में वे संवेदनशील डॉक्टर की भूमिका में थे, तो 'चुपके-चुपके' में वे उस प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी के रोल में थे, जिसने हल्की-फुल्की कॉमेडी से दर्शकों को गुदगुदाया। धर्मेंद्र के करिअर की विशिष्ट भूमिकाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा, नायकत्व और संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ किरदार बॉलीवुड के सबसे यादगार और प्रभावशाली माने जाते हैं। धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के तौर पर भी अपनी छवि बनाई। मेरा गांव मेरा देश, प्रतिज्ञा, जुगनू, समाधि, राजा जानी और 'हुकूमत' में साफ दिखाई दिया, जिससे वे 'ही मैन' कहे जाते रहे।

हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सितारों में धर्मेंद्र की गिनती होती रही है। उनका फिल्म करिअर छह दशकों से अधिक समय तक चला और उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1966 में 'फूल और पत्थर' से धर्मेंद्र को जबरदस्त लोकप्रियता मिली, इसके बाद वे 'एक्शन हीरो' और 'ही-मैन' के रूप में पहचाने गए। 1970 के दशक में वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में शामिल थे और एक साल में ही 9 से 12 फिल्में रिलीज़ होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा था। 'शोले' (1975) में वीरू के किरदार ने उन्हें सबसे बड़ी पहचान दी। लेकिन, वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। सत्यकाम, चुपके-चुपके, मेरा गांव मेरा देश, धरमवीर, सीता और गीता, द बर्निंग ट्रेन, हुकूमत, प्रतिज्ञा, नौकर बीवी का जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।

रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर समेत हर शैली की फिल्मों में उन्होंने सफलता पाई। लेकिन, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों ने उनके करिअर को नई ऊंचाई दी। 'सत्यकाम' और 'चुपके-चुपके' इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। धर्मेंद्र सिनेमा के ऐसे सितारा रहे, जिन्होंने अभिनय, एक्शन, रोमांस और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके अभिनय की विरासत फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा अमिट रहेगी। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में हास्य, जोश और भावुकता का अद्भुत मिश्रण पेश किया। दरअसल, उनकी ऐसी भूमिकाएं सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में गिनी जाती हैं। 'फूल और पत्थर' के शाका में वे नेकदिल इंसान के रोल में दिखाई दिए तो 'अनुपमा' का राम रोमांटिक और संवेदनशील चरित्र था, जिसका चर्चित काव्यात्मक अंदाज दर्शक आज भी नहीं भूले। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता रहे, जिन्होंने हर भूमिका, हर जॉनर में अपने अभिनय का जादू बिखेरा और हिंदी सिनेमा की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने अभिनय में उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा हर भूमिका में बेजोड़ अदाकारी की और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने 'फूल और पत्थर' और 'मेरा गांव मेरा देश' जैसी फिल्मों में सख्त और साहसी नायक का किरदार निभाया, वहीं 'चुपके चुपके' और 'प्रतिज्ञा' में हल्का-फुल्का रोल निभाया। इससे उनकी कॉमिक टाइमिंग सामने आई। 'शोले' में चुलबुले लेकिन निडर वीरू और 'अनुपमा' में विचारशील लेखक बनकर उन्होंने अपने अभिनय की गहराई को दर्शाया। 'हकीकत' जैसी फिल्म में युद्ध के दृश्यों और भावनाओं को, और 'लोफर' जैसी फिल्मों में रोमांटिक व कॉमिक किरदार को उन्होंने जीवंत बनाया।

धर्मेंद्र अपने अभिनय काल में 'ही मैन' के नाम से मशहूर रहे हैं। लेकिन, एक्शन के साथ भावनात्मक और हास्य भूमिका में भी वे उतने ही सशक्त दिखे। उनके करिअर में 300 से अधिक फिल्में दर्ज हैं। उनके खाते में पद्मभूषण जैसे सम्मान के साथ कई यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हैं। 1997 में फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन?होंने हर दौर में अपनी छवि को बरकरार रखते हुए फिल्मों में सक्रियता बनाए रखी। चरस, शोले, राजपूत, कातिलों के कातिल और 'समधी' आदि इसी का प्रमाण है। उनकी एक्टिंग स्टाइल में सहजता, इमोशन और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता हमेशा कायम रही। उनकी अभिनय शैली में समय के साथ गहरी परिपक्वता और विविधता आई। शुरुआती दौर में वे रोमांटिक और संवेदनशील किरदारों के लिए पहचाने गए।

वर्ष 1970 के दशक में एक्शन हीरो के रूप में उनका बोलबाला हुआ और बाद के सालों में उन्होंने भावनात्मक और चरित्र प्रधान भूमिकाएं की। धर्मेंद्र की छवि रोमांटिक हीरो और संवेदनशील पात्रों की भी रही। अनुपमा, बंदिनी और 'हकीकत' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय में मासूमियत, सहजता और कोमलता प्रमुख रही। लेखकों तथा निर्देशकों के निर्देशन में उन्होंने साहित्यिक, दार्शनिक और आदर्शवादी किरदारों को गहराई से निभाया। लेकिन, उनका शुरुआती समय संघर्ष से भरा रहा। 8 दिसंबर, 1935 को पंजाब में जन्मे इस कलाकार के फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से हुई थी। शुरू में उन्हें साधारण भूमिकाएं मिलीं, लेकिन जल्दी ही उनके अभिनय और व्यक्तित्व ने दर्शकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया।

उम्र बढ़ने के साथ धर्मेंद्र ने सपोर्टिंग और चरित्र प्रधान भूमिका निभानी शुरू की। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो, अपने और 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्मों में अपनापन, विनम्रता और हंसमुख अंदाज देखने को मिला। भावनात्मक दृश्य निभाने में नयापन और अनुभव की परछाई उनके अभिनय में साफ झलकी। धर्मेन्द्र के अभिनय का हर दौर, बदलते सामाजिक और फिल्मी चलनों के हिसाब से ढलता गया। कभी रोमांटिक, कभी एक्शन, कभी हास्य और अंत में पारिवारिक किरदारों में उनकी सादगी और गहराई दर्शकों के दिलों में आज भी ताजा है। इसी दौर में उनकी अनोखे किरदारों में आत्मविश्वास, ऊर्जा और 'ही-मैन' वाली मर्दानगी छवि जुड़ गई।

धर्मेंद्र की अभिनय यात्रा के सबसे यादगार पल 'शोले' में रहा। रोमांच से भरपूर उनकी वो अदाकारी धर्मेंद्र की सबसे लोकप्रिय छवियों में एक है। इसके अलावा 'सत्यकाम' का सत्यप्रिय, ईमानदार, आदर्शवादी और जज़्बाती किरदार में गहन भावुकता भी उनके करिअर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय क्षण माना जाता है। 'चुपके चुपके' में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का हास्य और मासूमियत के साथ उनके अभिनय ने क्लासिक कॉमेडी को नई जान दी। 'फूल और पत्थर' का शाका का जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस भी याद किया जाता है। एक रफ एंड टफ किरदार के साथ धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्मों में नायक की छवि को नया मोड़ दिया था। 'अनुपमा' में धर्मेंद्र के किरदार अशोक का सादगी और संवेदनशीलता से भरा किरदार उनके अभिनय की गहराई को दर्शाता है।

धर्मेंद्र के जीवन का सबसे श्रेष्ठ अभिनय ज़्यादातर आलोचकों की नज़र में फिल्म 'सत्यकाम' की भूमिका को माना जाता है। जबकि, लोकप्रियता के स्तर पर 'शोले' (वीरू) और 'चुपके चुपके' (परिमल) को भी उनकी शिखर-प्रदर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। आलोचकों के हिसाब से कई फ़िल्मी आलोचक इसे धर्मेंद्र के करिअर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहकर 'सत्यकाम' में उनके आदर्शवादी, अंदर से टूटे हुए नायक की भूमिका को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं।

लेकिन, अब इस हरफनमौला अभिनेता की हर भूमिका का खाता बंद हो गया। अब जबकि, धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें उनकी फिल्मों के किरदार से ही हमेशा याद किया जाता रहेगा।

2026 में वैश्विक आर्थिक मंदी की आहट

सनत कुमा र जैन

2026 की शुरुआत मे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बाज़ार विश्लेषकों और दुनिया भर की सभी केंद्रीय बैंकों ने चेतावनी दी है, कि दुनिया एक व्यापक आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। कई देशों में उत्पादन, निवेश और उपभोक्ता खर्च में भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसे वैश्विक आर्थिक मंदी का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, 2025 के अंत से शुरू हुई आर्थिक मंदी 2026 में और गहरी हो सकती है। अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अमेरिकी बाज़ार में नौकरी के अवसर 18 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं यूरोप में ऊर्जा की कीमतें और महंगाईदर उपभोक्ता खर्च को बढा रही हैं। जिसके कारण यूरोप में भी लगातार मांग घटती चली जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर ब्याज दरों में राहत नहीं मिली, तो स्थिति तेजी के साथ बिगड़ सकती है। एशियाई देशों में भी हालात बेहतर नहीं हैं। चीन की आर्थिक सुस्ती का असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। चीन के रियल- स्टेट और विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी ने वैश्विक व्यापार को धीमा कर दिया है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्यात कम होने से विनिर्माण गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। जापान और दक्षिण कोरिया में भी आर्थिक विकासदर ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत मे भी वैश्विक मंदी का दबाव दिखने लगा है। हालांकि भारत की घरेलु मांग स्थिर बनी हुई है। लेकिन निर्यात में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, विदेशी निवेश में कमी, विदेशी निवेशकों का सावधानी का रुख भरतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। आईटी, वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट

और फार्मा जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों मे विदेशी मांग में कमी देखी जा रही है। कृषि क्षेत्र में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों के उतार-चढ़ाव ने अनिश्चितता को ओर बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है, अगर यह स्थिति कुछ माह और देखने को मिली, तो रोजगार और छोटे उद्योगों पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है।

वित्तीय बाज़ारों की हलचल तेज़ हो गई है। शेयर बाज़ारों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों का भरोसा क्रिप्टोकरंसी और शेयर बाजार में कमजोर हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, वैश्विक मंदी का असर कम करने के लिए दुनिया के सभी देशों को नीतिगत सहयोग और समन्वय बनाने की जरूरत होगी। ग्रीन एनर्जी, तकनीकी नवाचार और वैकल्पिक सप्लाई चेन मे निवेश से अर्थव्यवस्था को फौरी तौर पर कुछ राहत मिल सकती है। इस समय दुनिया के अर्थशास्त्रियों की निगाहें प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों और उनके द्वारा अगले कौन से कदम उठाए जाएंगे इस पर टिकी हैं। जिस तरह से दुनिया के सभी देशों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है, अमेरिका ने जिस तरह के टेरिफ वार की शुरुआत की है उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर के देशों में अनिश्चितता बढ़ी है। दुनियाभर के सभी देशों के ऊपर कर्ज का भार पिछ्ले एक दशक में तेजी के साथ बड़ा है। सरकारी खजाने की बड़ी रकम कर्ज की अदाएगी और ब्याज में जा रही है। पिछ्ले एक दशक में दुनियाभर के देशों के नागरिकों पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। आय मे कमी आई है। महंगाई के कारण आम आदमी की मांग घट रही है, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस बात की आशंका आर्थिक विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं खुलकर कहने लगी हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार 2026 आर्थिक मंदी का साल होगा। इसमें शेयर बाजारों में भी भारी उथल-पुथल होगी। इसका असर वैश्विक स्तर पर पडना तय है।

भारतीय संस्कृति में निहित कर्तव्यबोध की अभिव्यक्ति

प्रो.डॉ.भारत

छब्बीस नवंबर का दिन भारतीय गणतंत्र के इतिहास में केवल संविधान अंगीकरण का उत्सव भर नहीं है, यह उन मूलभूत मूल्यों के पुनर्स्मरण का अवसर भी है, जिन पर हमारे लोकतंत्र की आत्मा टिकी हुई है। भारतीय संविधान केवल विधिक प्रावधानों का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक नैतिक संकल्प है... एक ऐसी मूल्य-व्यवस्था का घोषणापत्र है जो देश, समाज और व्यक्ति के संबंधों को संतुलन, न्याय और कर्तव्य के ढांचे में देखती है। इसी संदर्भ में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय संविधान की नैतिक चेतना का आधार-स्तंभ है। गीता का यह प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक स्तर पर है। वह भारतीय मानस में सदियों से प्रवाहित उस दृष्टि का संहिताबद्ध रूप है, जिसने संविधान निर्माताओं की मूल्य-चेतना को आकार दिया।

संविधान की प्रस्तावना में 'न्याय', 'स्वतंत्रता', 'समानता' और 'बंधुत्व' जैसे शब्द केवल विधिक संकल्प नहीं हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों का दार्शनिक प्रतिपादन हैं। यह मूल्य किसी बाहरी प्रभाव से नहीं आए, वे भारतीय परंपरा की लंबी साधना में विकसित हुए हैं। संविधान सभा की चर्चाओं में कई सदस्यों ने बार-बार यह रेखांकित किया कि संविधान की आत्मा को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के मूल में निहित 'कर्तव्य-बोध' को देखना आवश्यक है।

गीता का यह विशिष्ट योगदान है कि वह 'कर्तव्य' को किसी पुरस्कार, निजी-लाभ या भावनात्मक दबाव से ऊपर रखकर उसे समाज के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करती है। यही दृष्टि आगे चलकर संविधान के 'भाग-4क' में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों के रूप में प्रकट होती है। यद्यपि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को संविधान के बयालीसवें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बाद में जोड़ा गया था तथा इसे 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया था।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों ने नैतिक राजनीति का जो प्रतिमान स्थापित किया था उसका केंद्र-बिंदु कर्तव्य, आत्मानुशासन व लोककल्याण था और वह गीता-दृष्टि से ही अनुप्राणित था। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यही नैतिक विचार संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों का भी मार्गदर्शन करता था।

जब संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो उसके पीछे यही भारतीय दृष्टि थी कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। गीता में यह नैतिक आग्रह स्पष्ट दिखाई देता है कि बिना कर्तव्य-पालन के कोई व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। संविधान भी यही संदेश देता है कि नागरिक के अधिकार उसकी कर्तव्य-निष्ठा से सशक्त होते हैं, कमज़ोर नहीं।

भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र के शासन का आधार केवल अधिकारों की बहुलता नहीं है, बल्कि संतुलन की व्यवस्था है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की त्रि-संरचना संतुलन और विवेक पर आधारित है। गीता में जो जीवन-दृष्टि मिलती है, वह अतिरेक व अतिवाद से बचने और मध्यमार्गीय बुद्धि को अपनाने की शिक्षा देती है। संविधान में 'युक्तियुक्त विवेक', 'नैतिकता', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'विवेकपूर्ण संतुलन' जैसे सिद्धांत इसी नैतिक परंपरा से प्रेरित जान पड़ते हैं। यह दृष्टि भारतीय संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं रहने देती, बल्कि उसे मूल्य-निष्ठ शासन की आधारशिला बनाती है।

भारतीय परंपरा में समाज के कमजोर, पीड़ित, वंचित और हाशिए पर खड़े व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व हमेशा से शासन पर रहा है। गीता में वर्णित दृष्टि यह मानती है कि समाज का वास्तविक धर्म वही है जो दुर्बलों की रक्षा करे, न्याय को प्राथमिकता दे और जीवन में संतुलन स्थापित करे। संविधान का उद्देश्य भी यही है कि ऐसा समाज बनाया जाये जिसमें व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो और राज्य लोककल्याण को अपना कर्तव्य समझे।

संविधान न केवल नागरिकों को, बल्कि शासन-तंत्र को भी उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाता है। शासन का लक्ष्य 'सेवा' है। गीता के अनुसार भी नेतृत्व वह है जो दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, समाज की भलाई को प्राथमिकता दे और निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रखे। यही नेतृत्व-दृष्टि भारतीय लोकतंत्र को स्वस्थ और जीवंत बनाती है। जब एक प्रशासक, न्यायाधीश, विधिनिर्माता या जनप्रतिनिधि इस नैतिक दृष्टि को अपनाता है, तो संविधान की आत्मा कार्यान्वित होती है और जब यह दृष्टि खो जाती है, तो संवैधानिक संस्थाएं केवल औपचारिक संरचनाएं बनकर रह जाती हैं।

अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता के साथ संयम और विविधता के साथ सहिष्णुता... ये सभी संविधान की उसी नैतिक परंपरा से निकले हैं, जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि गीता ने दी है। जब समाज इस चेतना को भूलता है, तो कानून की संख्या बढ़ती है, किंतु व्यवस्था कमजोर हो जाती है।

आज संविधान दिवस आत्ममंथन का अवसर है... क्या हम संविधान की उस नैतिक दृष्टि के अनुरूप चल रहे हैं जिसने हमें दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र बनाया? क्या हम अधिकार मांगते समय अपने कर्तव्यों को भी याद रखते हैं? क्या प्रशासन और राजनीति पारदर्शिता और सेवा की भावना पर चल रही है? क्या हम समानता, न्याय और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हमें बताता है कि संविधान कितनी गहराई से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है।

प्याज की अर्थी सजाई, बैंड-बाजे के साथ निकाली शवयात्रा

माही की गूंज, मंदसौर।

जब दुख हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अपने दर्द को जताने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला दृश्य मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखने को मिला, जहां किसानों ने प्याज की अर्थी सजाकर, बैंड-बाजों के साथ उसकी शवयात्रा निकाली।

गिरते दामों से परेशान किसानों ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए बताया कि, किस तरह उनकी मेहनत की मेहनत मिट्टी हो रही है। वीडियो में साफ दिखता है कि किसान अपने दर्द को आवाज देने के लिए किस हद तक मजबूर हो चुके हैं।

गिरते दामों से नाराज होकर किसानों ने उठाया कदम

मंदसौर से एक अनोखा और बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। प्याज के गिरते दामों से नाराज किसानों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसानों ने प्याज को किसी मृत देह की तरह सम्मान देकर उसकी अर्थी सजाई और फिर बैंड-बाजों के साथ अंतिम यात्रा निकाली।

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बोरी से प्याज निकालकर उसे एक लकड़ी की अर्थी पर रखा गया। इसके बाद उस पर सफेद कपड़ा डालकर उसे किसी शव की तरह बांधा गया। फिर उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई, फूल अर्पित किए गए और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई।

बैंड-बाजों के साथ किया प्याज का अंतिम संस्कार

जैसे किसी इंसान की अंतिम यात्रा में एक छोटा मटका जलाकर लेकर जाया जाता है, उसी तरह किसानों ने एक मटके में आग जलाकर उसे अर्थी के साथ आगे चलाया। बैंड-बाजों की धुन बज रही थी, लोग अर्थी के साथ चल रहे थे और प्याज को मानो किसी प्रियजन का दर्जा देकर श्मशान घाट तक ले जाया गया।

श्मशान घाट पहुंचकर किसानों ने प्याज का अंतिम संस्कार भी किया। उनका कहना है कि, बाजार में प्याज के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनकी उपज मर चुकी है, मेहनत, खर्च, मजदूरी सब व्यर्थ हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्याज पर उचित दाम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वह कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोग किसानों के दर्द से सहानुभूति जताते दिखे, तो कुछ ने सरकार से सवाल पूछे।

ट्रक से खुलेआम वसूली, पुलिसकर्मी खड़े होकर देखते रहे

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के मक्सी थाने के सामने रोड किनारे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि यह स्पष्ट नही हो सका है कि ट्रक सवार लोगों से रुपए लिये जा रहे हैं या कुछ और।

वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाहन रोड किनारे खड़ा है। एक पुलिसकर्मी वाहन में बैठा है और एक पुलिसकर्मी वाहन के पास घूम रहा है। वहीं एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे ट्रक सवार लोगों से कुछ लेनदेन कर रहा है।

जांच की बात कही

मामले में शाजापुर एसपी यशपालसिंह राजपूत ने जांच कराने की बात कही है। मक्सी थाना टीआई संजय वर्मा का कहना है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सेवानिवृत होमगार्ड सैनिक है। मौके पर खड़े पुलिसकर्मियों का मामले से कोई संबंध नहीं होने की बात उन्होंने कही। वह बोले की सेवानिवृत होमगार्ड सैनिक को सख्त लहजे में समझाइश दी गई है।

हालांकि मामले में सवाल यह उठाया जा रहा है कि अगर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का अवैध लेनदेन से कोई संबंध नही है तो उन्होंने अवैध लेनदेन कर रहे व्यक्ति क्यों नहीं रोका। आखिर उनकी मौजूदगी में थाने से चंद कदम दूरी पर कोई व्यक्ति कैसे वाहन सवार लोगों से अवैध वसूली कर सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे ट्रकों के पास जाता है और ट्रक में सवार व्यक्ति उसे हाथ में कुछ पकड़ाते दिख रहे हैं।

कहा जा रहा है कि मक्सी में शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक हाट में आने वाले ट्रकों से एंट्री वसूली जाती है। वीडियो में मौके पुलिस वाहन खड़ा दिख रहा है, जिसमें ड्रायविंग सीट पर पुलिसकर्मी बैठा है और एक पुलिसकर्मी वाहन के पास मौजूद दिख रहा है। वहीं, एक व्यक्ति सादे कपड़ों में है और वहां से गुजर रहे ट्रक सवार लोगों से कुछ लेनदेन कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति से माना जा रहा है कि अवैध वसूली को पुलिस का संरक्षण है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी इसमें संलिप्त है। हालांकि स्पष्ट वीडियो होने के बावजूद अब तक संबंधितों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात, चेकिंग में और कड़ाई

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में विशेष रात्रि एवं प्रभात सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के सभी अनुभागों में सुरक्षा सतर्कता बढ़ाते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।

शाम से ही संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट्स स्थापित कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। साथ ही सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक विशेष प्रभात गश्ती पार्टियाँ भी सक्रिय की गई हैं।

शहर सुरक्षा की त्रिस्तरीय निगरानी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम शहर राकेश खाखा के मार्गदर्शन में प्रत्येक रात्रि में डीएसपी स्तर के अधिकारी रात्रिकालीन गश्त प्रभारी के रूप में शहर में भ्रमण करेंगे। संबंधित थाने के उपलब्ध बल के अतिरिक्त 2 निरीक्षक स्तर के अधिकारी शहर की सुरक्षा में गश्त अधिकारी के रूप में भ्रमण पर रहेंगे। प्रत्येक थाना क्षेत्र में संबंधित थाने से उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी बल के साथ थाना क्षेत्र में गश्त करेंगे। प्रत्येक रात्रि एक निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी विशेष रूप से प्रशासनिक भवनों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा देखेंगे। पुलिस लाइन से एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी बल के साथ अतिरिक्त रूप से हाईवे गश्त पर तैनात रहेंगे।

शाम से मध्य रात्रि तक विशेष चेकिंग

अनावश्यक रूप से घूमने वाले असामाजिक तत्वों, अवैध हथियार रखने वालों, तेज रफ्तार व तीन सवारी वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल लगाया गया है।

मुख्य चेकिंग पॉइंट्स

रतलाम शहर के मुख्य चेकिंग पॉइंट्स सालाखेड़ी फांटा, करमदी फांटा, मेडिकल तिराहा, वरोठ माता मंदिर, फव्वारा चौक पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा। रतलाम ग्रामीण अनुभाग के महत्वपूर्ण पॉइंट्स चिकलिया टोल बिलपांक, बड़ौदा फांटा नामली, शिवगढ़ थाने के सामने चेकिंग पॉइंट्स लगाकर अतिरिक्त बल तैनात किया है।

ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था भी और सुदृढ़

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में जावरा शहर, जावरा ग्रामीण एवं आलोट अनुभाग में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त बल के साथ गश्त व्यवस्था मजबूत की गई है।

मुख्य ग्रामीण चेकपॉइंट्स

सैलाना- पिपलौदा फांटा, रानीसिंग चौराहा, बिरसामुंडा चौराहा, बाजना थाने के सामने, सरवन-कुंडा टोल बैरियर

जावरा- बहादुरपुर रोड, जोयो होटल तिराहा, चिकलाना फांटा

जावरा ग्रामीण- प्रतापगढ़ रोड तिराहा, आरटीओ बैरियर, माननखेड़ा, बड़ावदा थाने के सामने

आलोट - बड़ौद नाका, ताल फांटा, चंबल नदी पुलिया बरखेड़ा

तकनीक और गश्ती-दोनों पर समान फोकस

* सभी चार पहियां वाहन चिह्नित नोडल पॉइंट्स का नियमित भ्रमण करेंगे
* अनुविभागीय अधिकारी अपने स्तर पर हॉटस्पॉट क्षेत्र चिह्नित कर उस पर अतिरिक्त बल तैनात करेंगे
* सीसीटीवी कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी

पुलिस अधीक्षक ने किया रात्रि गश्त का निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने गत रात्रि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि संदिग्धों की गहन तलाशी सुनिश्चित करें। अनावश्यक जमावड़ा रोकें। तेज रफ्तार एवं तीन सवारी वाहनों पर सख्ती बरतें। असामाजिक तत्वों पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई करें।

नागरिकों से अपील

यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम थाने को सूचित करें।

युवक ने पानी मशीन समझकर बोतल क्रेशर में डाल दिया हाथ

शहडोल। मध्य प्रदेश में एक युवक को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ गया। यहां के शहडोल रेलवे स्टेशन पर युवक ने बोतल क्रेशर को पानी की मशीन समझकर गलती से हाथ डाल दिया। जिससे उसका हाथ बोतल क्रेशर में फंस गया। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मेडिकल टीम भी पहुंच गई और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मशीन से हाथ को बाहर निकाला। लेकिन तब तक हाथ कुचल चुका था। ऐसे में डॉक्टरों को जान बचाने के लिए पंजा भी काटना पड़ गया।

यह पूरा मामला शहडोल रेलवे स्टेशन का है। जहां उमरिया जिले के मानपुर का रहने वाला 25 वर्षीय सौरभ गुप्ता स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसने प्लेटफॉर्म पर लगी बोतल क्रेशर को पानी की मशीन समझ लिया और गलती से हाथ डाल दिया। जिससे अगले ही सेकंड मशीन के तेज़ ब्लेड उसके हाथ को अंदर की ओर खींचते चले गए।

सौरभ दर्द से तड़पकर चीखने लगा। जिसपर फौरन आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की मेडिकल टीम भी पहुंच गई। लेकिन सौरभ का हाथ इतनी गहराई में फंस गया था कि उसे निकालना लगभग नामुमकिन लग रहा था।

3 घंटे तक हाथ को बाहर निकालने का रेस्क्यू चला और कटर से मशीन को काटा गया। फिर काफी मशक्कत के बाद उसका हाथ बाहर निकला। उसका हाथ बुरी तरह कुचल चुका था जिसके चलते उसकी जान बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को हाथ का पंजा काटना पड़ा।

शहडोल जीआरपी थाना प्रभारी आरएम झरिया ने बताया कि, एक युवक ने पानी की मशीन समझकर बोतल क्रेशर में हाथ डाल दिया था। जिससे उसका हाथ अंदर फंस गया और करीब 3 घंटे बाद हाथ निकला। लेकिन तब तक हाथ बुरी तरह कुचल गया था। ऐसे में उसकी जान बचाने के लिए हाथ के पंजे को काटना पड़ा।

5वें दिन भी थाने पर प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने मांगा आरोपी सलमान का एनकाउंटर

रायसेन।

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी मांग को लेकर पांचवें दिन भी गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। महिलाओं के साथ-साथ हिंदू संगठन और स्थानीय लोग गौहरगंज थाने के बाहर डटे हुए हैं। इसको लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं और पुरुष आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इस बीच फरार आरोपी सलमान पर इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है।

रायसेन की घटना पर सरकार भी सख्त हो गई है और सीएम मोहन यादव ने डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम ने नाराज़गी जताई और मंडीदीप में 10 किलोमीटर के चक्काजाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई से भी नाराज दिखे।

इसके बाद सीएम मोहन यादव ने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। 'आजतक' से बात करते हुए रायसेन डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगाई गई हैं। कुछ इनपुट्स पुलिस को मिले हैं जिसके आधार पर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

बता दें कि, 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी 23 साल का आरोपी सलमान उर्फ नजर उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल में ले गया और यहां बच्ची से दुष्कर्म कर भाग गया। बाद में बच्ची खून से लथपथ हालत में जंगल में मिली थी। हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है।

'मृत' व्यक्ति की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे आदिवासी

माही की गूंज, रतलाम।

मेडिकल कॉलेज में आदिवासियों की एक टोली मृत व्यक्ति की 'आत्मा' लेने पहुंची। ढोल और थाली बजाते हुए महिला-पुरुष अस्पताल के अंदर घुस गए, जहां करीब एक घंटे तक पूजा-पाठ का अंधविश्वास का खेल चलता रहा।

यह टोली झावनी झोड़िया गांव से आई थी और तीन महीने पहले मेडिकल कॉलेज में कीटनाशक पीने से मरे शांतिलाल झोड़िया की आत्मा को लेने आई थी, जिसे वे अपने गांव में ओटला बनाकर देवता के रूप में स्थापित करेंगे।

एक घंटे तक चला खेल

रतलाम मेडिकल कॉलेज में करीब एक घंटे अंधविश्वास का खेल चलता रहा। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम करीब 4 बजे आदिवासियों की एक टोली मृत व्यक्ति की 'आत्मा' लेने पहुंची। ढोल और थाली बजाते महिला-पुरुष भीतर घुस गए। महिलाएं गीत गा रही थीं। एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा था। एक शख्स के सिर से खून बह रहा था। हाथों में पूजा की सामग्री थी।

आत्मा लेने पहुंची भीड़

अस्पताल में जिसने भी यह नजारा देखा, वहीं रुक गया। पूछने पर पता चला कि तीन महीने पहले गांव के शांतिलाल झोड़िया की मौत मेडिकल कॉलेज में हो गई थी। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण, आदिवासी मान्यता के अनुसार उसकी आत्मा को लेने आए हैं। उसे देवता के रूप में गांव में ओटला बनाकर स्थापित करेंगे। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास तो कुछ ने परंपरा कहा है।

आदिवासी समाज में परंपरा

टोली में शामिल एक शख्स ने बताया- आदिवासी समाज में आकस्मिक मौत होने पर परिजन उसी जगह जाते हैं, जहां परिवार के सदस्य की मौत हुई है। वहां जाकर आत्मा से अपने साथ चलने का आह्वान किया जाता है। उसे पत्थर, लकड़ी या अन्य रूप में अपने साथ लेकर गांव के किसी स्थान या खेत में ओटला बनाकर देवता के रूप में स्थापित किया जाता है। एक महिला ने सिर पर टोकरी रखी थी, इसमें एक पत्थर था।

कीटनाशक पीने से 3 महीने पहले हुई थी मौत

झावनी झोड़िया गांव के ग्रामीण जिस मृतक की आत्मा को लेने आए थे, उसका नाम शांतिलाल झोड़िया था। कीटनाशक पीने से उसकी तीन माह पहले मौत हो गई थी। परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। वे भी मेडिकल कॉलेज आए थे। मृतक की बुआ नीता झोड़िया ने बताया- मेरे भतीजे शांतिलाल की मौत हो गई थी। अब वह बड़े भाई की बेटी के शरीर में आकर उसे परेशान कर रहा है। बोल रहा है कि मुझे मेडिकल कॉलेज से लेकर आओ, इसलिए हम सब उसे लेने आए हैं। पत्थर में उसकी आत्मा को लेकर जा रहे हैं।

किसी ने रोका भी नहीं

मेडिकल कॉलेज में करीब एक घंटे तक रुकने के बाद परिजन गांव के लिए निकल गए। इस दौरान साथ में आए ग्रामीण ढोल और थाली बजाते रहे। गौरतलब बात ये है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में गार्ड, मरीजों के अटेंडर के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देते। ऐसे में करीब 10 लोग हाथों में नारियल, पूजा सामग्री लेकर बेधड़क अंदर घुसे और पूजा-पाठ की। अंधविश्वास का ये खेल बेधड़क चलता रहा लेकिन इन्हें किसी ने भी नहीं रोका।

काम घटिया हुआ तो ठेकेदार को कर दूंगा ब्लैकलिस्टेड - मंत्री राकेश सिंह

माही की गूंज, खंडवा।

बुधवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने ओंकारेश्वर और पंधाना क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान 115 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों और पुल पुलियों की नींव रखी गई। कार्यक्रम के मंच से मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई तो ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी शिकायत मिले, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

मंत्री सिंह ने कहा कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद अभियंता और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। जनता का पैसा व्यर्थ न हो, इसलिए ऐसे सख्त कदम आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में विकास की सोच नहीं थी। यदि होती, तो 58 वर्षों की सरकार में सड़क विकास किया जा सकता था, लेकिन एक मार्ग को दो लेन करना तो दूर, एकल मार्ग भी ठीक तरह से नहीं बनाए गए। सड़क निर्माण में अब पेड़ कटाई की बजाय पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे प्रत्येक किलोमीटर पर भूजल पुनर्भरण के लिए जल ग्रहण संरचना बनाई जाएगी, ताकि पानी व्यर्थ न बह सके।

पंधाना खंडवा मार्ग का भूमिपूजन किया गया, जिसके निर्माण पर 52 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय होंगे और इसके निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ओंकारेश्वर में 18 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से बर्फानी आश्रम तक पहुँच मार्ग सहित तीन छोटे पुलों के निर्माण का भूमिपूजन किया गया।

इसके अलावा 8 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सर्किट हाउस निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। ओंकारेश्वर के नर्मदा तट पर तरंग आधारित जेट्टी प्रणाली, गोमुख घाट, बाणगंगा घाट और ब्रह्मपुरी घाट पर 49 लाख 74 हजार रुपये की लागत से निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

कांग्रेस ने संविधान की रक्षा का लिया संकल्प

माही की गूंज, खरगोन।

संविधान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस समिति द्वारा सब्जी मंडी बगीचे स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सुबह शहर और जिले के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और बाबा साहब की प्रतिमा को नमन करते हुए जयकारे लगाए।

कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प दिलाया। नाईक ने कहा कि भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है, जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि संविधान ने नागरिकों को अधिकारों के साथदृसाथ उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे संविधान की मूल भावना का सम्मान करें और उसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने में सहयोग दें। जिलाध्यक्ष नाईक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब के विचारों का समर्थन करती आई है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी।

कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस समिति के पदाधिकारी, पार्षद व अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

युवक पर आदिवासी युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

माही की गूंज, सेंधवा।

युवक पर आदिवासी युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और लव जिहाद में फँसाने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर युवती के परिजन, हिन्दू संगठन और आदिवासी संगठन शहर थाना पहुँचकर उप-अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

परिजनों ने बताया कि शहर में रहने वाला तौसीफ युवती को अपने साथ ले गया है। आरोप है कि युवक और उसका परिवार युवती का मस्तिष्क-प्रक्षालन (ब्रेनवॉश) कर धर्म परिवर्तन और विवाह का दबाव बना रहा है। परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और कठोर कार्रवाई की मांग की।

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ. रेलाश सेनानी ने घटना को गंभीर बताते हुए युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) के खंड अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने ज्ञापन में तौसीफ के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। साथ ही युवती को नारी निकेतन भेजकर उसकी परामर्श (काउंसलिंग) कराने की बात कही।

शहर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि युवती बालिग है और उसे फिलहाल सुरक्षित वन-स्टॉप केंद्र में रखा गया है। पुलिस ने युवती से बातचीत की है और उसने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि यदि युवती यह शिकायत करती है कि उस पर जबरन धर्म परिवर्तन या विवाह का दबाव है, तो पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। फिलहाल परिजनों और संगठनों के ज्ञापन के आधार पर जाँच जारी है।

संभावित तनाव को देखते हुए शहर थाने में अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई। चार थाना प्रभारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। उप-अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अजय वाघमारे और थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने परिजनों और संगठनों के प्रतिनिधियों से लगभग एक घंटे तक चर्चा की, जिसके बाद स्थिति शांत रही और कोई हंगामा नहीं हुआ।

भाकनि ने कपास खरीदी के नियम बदले

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले में भारतीय कपास निगम (भारतीय कॉटन निगम) अब किसानों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर कपास की खरीदी करेगा। पहले प्रति हेक्टेयर 14.01 क्विंटल के तय मापदंड पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। किसानों ने अधिक उत्पादन होने के बावजूद पुराने मापदंड के कारण खरीदी प्रक्रिया का विरोध जताया था। नए आदेश से किसानों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के अनुसार खरीदी के लिए कपास की उत्पादकता का प्रमाण पत्र संबंधित कृषि अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

उप संचालक कृषि एस.एस. राजपूत ने बताया कि उत्पादन प्रमाण पत्र क्षेत्र के कृषि अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। बड़वाह में रेखा शाह और कविता शाह, जबकि खरगोन में किसान दिनेश पटेल को कपास उत्पादन प्रमाण पत्र जारी कर खरीदी की गई है। खरगोन मंडी में प्रतिदिन 10 हजार क्विंटल से अधिक कपास की आवक हो रही है। मंगलवार को 12,600 क्विंटल कपास आया, जिसके भाव 5 हजार से 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान संगठनों ने इस निर्णय को अपने आंदोलन के दबाव का परिणाम बताया है। भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि किसानों की समस्याओं को लेकर 1 दिसम्बर को खलघाट में निमाड़ क्षेत्र का बड़ा किसान आंदोलन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियाँ जारी हैं।

सरकारी स्कूल के पीछे मिला आठ फीट लंबा अजगर

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी थाना क्षेत्र के बड़गांव गाँव में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय के पास आठ फीट लंबा और लगभग बीस किलोग्राम वजनी अजगर मिला। बुधवार दोपहर खेत की ओर जा रहे किसान रघुराज ने स्कूल के पीछे इस विशालकाय अजगर को देखा, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी।

किसान रघुराज ने बताया कि वे अपनी फसल की निगरानी के लिए खेत जा रहे थे। तभी उनकी नजर गाँव के रास्ते पर स्थित सरकारी विद्यालय के ठीक पीछे लेटे हुए अजगर पर पड़ी। अजगर का आकार और वजन देखकर स्थानीय लोग भयभीत हो गए। अजगर मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी।

सूचना पर वन विभाग की टीम गजेन्द्र सिंह बामनिया और दीपक सोलंकी के साथ मौके पर पहुँची। टीम ने विशेष उपकरणों का उपयोग कर अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर बचाव कार्य पूरा किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे कोई चोट न पहुँचे।

वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि यह 'जालीदार अजगर' (रेटिकुलेटेड पाइथन) प्रजाति का साँप है, जो कभीदृकभी जंगलों से भटककर खेतों या आबादी वाले क्षेत्रों में पहुँच जाता है। अजगर को सुरक्षित रूप से बावनगजा के जंगल में छोड़ दिया गया है।

वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराएँ नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि वन्यजीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आचरण का हिस्सा बने संविधान की भावना

पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी ऐसी दो तिथियां हैं जब तिरंगा लहरा कर अपना देश-प्रेम प्रकट करना हमें ज़रूरी लगता है। इसमें पहली तिथि (15 अगस्त, 1947) तो वह है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और दूसरी (26 जनवरी, 1950) हमें अपने लिए एक संविधान बनाने की याद दिलाती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अनुसार हमने अपना जीवन संचालित करने का संकल्प किया था। इसी संदर्भ में एक तिथि और भी है जो हमें अपने संविधान के प्रति निष्ठा की याद दिलाती हैकृवह तिथि है 26 नवम्बर। वर्ष 1949 में इसी दिन हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था, जो दो माह बाद देश पर लागू हुआ।

हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी माने जाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर, दस साल पहले, भारत सरकार ने 26 नवम्बर को संविधान-दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। तब से हर साल इस दिन कृतज्ञ राष्ट्र अपने संविधान-निर्माताओं को याद करता है, और यह संकल्प दुहराता है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर एक नया समाज बनायेंगे। यह भी शपथ ली जाती है कि हम सांविधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। पर क्या हम यह काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं?

हमारा संविधान हमें सिखाता है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग का क्यों न हो, समान है। समता के इस सिद्धांत का मतलब है भारतीय गणतंत्र का हर नागरिक संविधान की दृष्टि में किसी अन्य से किसी भी तरह कमतर नहीं है। सबके अधिकार बराबर हैंकृ और सबके कर्तव्य भी। इस समता के अभाव में न स्वतंत्रता का कुछ अर्थ रह जाता है और न ही न्याय और बंधुता का। अब हमें अपने आप से यह पूछना है कि समता के इस मानदण्ड पर हम कितने खरे उतरते हैं।

जिस जनतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपने लिए स्वीकारा है उसमें मतदान का बहुत व्यापक अर्थ है, और बहुत बड़ा अर्थ है। मतदान के द्वारा हम न केवल उनका चुनाव करते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व अथवा नेतृत्व करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हम न्याय और बंधुता के पक्ष में खड़े है; हम सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं, अपने ही जैसे दूसरे नागरिकों के कल्याण के बारे में भी सोचते हैं। मतदान वस्तुतः व्यक्तियों का नहीं, एक व्यवस्था का चुनाव है। यह बात समझने और स्वीकारने के बाद हमें यह सोचना है कि मतदान केंद्र पर जाकर हम जो वोट डाल आये हैं, क्या वह उन आदर्शों और मूल्यों के पक्ष में हुआ है या फिर अपने स्वार्थों और अपनी अज्ञानता के चलते हम कोई घटिया समझौता कर आये हैं? ऐसा कोई भी समझौता किसी अपराध से कम नहीं होता। इसलिए, पेटी में वोट डालने अथवा मशीन का बटन दबाने से पहले जागरूक मतदाता को दस बार सोचना चाहिए कि उसका यह कार्य उस संविधान के अनुरूप है या नहीं जिसने हमें मतदान का अधिकार दिया है?

बहुत अच्छा है हमारा संविधान। एक पूरा जीवन-दर्शन झलकता है इसमें। हमारे संविधान-निर्माताओं ने हर बात को बड़ी गहराई और विस्तार से सोचा है। पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को, यानी संविधान स्वीकार किये जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने चेताया था, 'संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह विफल हो जायेगा।' बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है संविधान सभा में दिये गये उनके इस भाषण को। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि समानता और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तीसरी चेतावनी जो उन्होंने देशवासियों को दी थी, वह यह थी कि राजनीति में व्यक्ति-पूजा तानाशाही की ओर ले जाती है।

सवाल उठता है क्या हमारे संविधान के शिल्पी की इन बातों के बारे में हम कभी सोचते हैं? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में नहीं है। हम और हमारे नेता संविधान के प्रति आदर दिखाने में भले ही पीछे न रहते हों, पर संविधान को सिर झुकाना और बात है, संविधान के प्रति ईमानदारी से निष्ठावान होना और बात। हमने अपने बड़े-बड़े नेताओं को, सबसे बड़े नेता को भी, न जाने कितनी बार संविधान की कस्में खाते देखा है, हमारे नेता यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि देश का संविधान उनके लिए सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है। पर इस सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? संविधान समानता की बात करता है, हमारे नेता असमानता की होड़ में लगे दिखाई देते हैं; संविधान कहता है धर्म या जाति के आधार पर देश में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए, हमारे नेता धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने में लगे रहते हैं। मेरा धर्म और तेरा धर्म की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'रघुपति राघव राजाराम' वाले भजन में 'ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम' क्यों जोड़ दिया था! हमारा संविधान देश के नागरिकों के बीच बंधुता के आदर्श की दुहाई देता है, हम इस आदर्श की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं!

डॉक्टर अम्बेडकर ने प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और परम्पराओं का हवाला देते हुए चेताया था, लोकतंत्र का यह सुनहरा इतिहास अब बीते कल की बात होकर रह गया है। अब हमें नये सिर से एक नये लोकतंत्र को सजाना है, उसे मज़बूत बनाना है। उन्होंने कहा था अपना यह प्राचीन लोकतंत्र हम एक बार खो चुके हैं, डर है, फिर न खो बैठें। सवाल उठता है वह डर हमें क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए यह डर। और फिर इस डर से मुकाबला करने की एक उमंग भी जगनी चाहिए हमारे भीतर।

जब हम अपने जनतांत्रिक संविधान की दुहाई देते हैं तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'इस नये पैदा हुए जनतंत्र के लिए इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जनतंत्र का ढांचा तो बना रहे पर वास्तविकता यह हो कि तानाशाही उसकी जगह ले ले।'

विश्ननाथ सचदेव

इन सारे खतरों के बारे में लगातार सोचते रहने की आवश्यकता है। काल्पनिक नहीं हैं ये खतरे। हम मान कर चल रहे हैं कि हमारे जनतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बहुत मज़बूत है हमारी बुनियाद। पर यह मज़बूती खोखली भी सिद्ध हो सकती है। मज़बूत जनतंत्र का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों में विश्वास करने वाला जनतंत्र। सच तो यह है कि तभी यह सही मानों में जनतंत्र कहला सकता है जब हमारे संविधान के ये चार स्तम्भ हमारी सोच और विश्वास का, हमारे व्यवहार का हिस्सा बनें। जब हम समता की बात करें तो वह एक भारतीय समाज की उदाहरण हो; जब हम स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता के सारे प्रतिमान दृष्टिगोचर होते हों, जब हम न्याय की बात करें तो वह हर क्षेत्र में हर भारतीय को मिलने वाला न्याय हो। तब, और सिर्फ तब, हम सही अर्थों में संविधान दिवस मनाने के अधिकारी होंगे।

लेकिन समाज को बांटने वाली जो स्थितियां आज देश में दिख रही हैं, कोई धर्म की दुहाई दे रहा है, कोई जाति के नाम पर समर्थन मांग रहा है, उससे एक भय-सा लगने लगा है। विश्व कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक भय-मुक्त वातावरण में अपने देश के उदय होने की प्रार्थना की थी, वह प्रार्थना तभी पूरी हो सकती है, जब हम समाज को बांटने वाली ताकतों को सफल न होने दें। नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का तकाज़ा है कि हम अपने संविधान की भावना को अपने आचरण का हिस्सा बनायें। इस संदर्भ में अभी जो दिख रहा है, वह कुल मिलाकर निराश ही करने वाला है। ज़रूरी है कि हम इस अवधारणा को अपनी सोच और व्यवहार का हिस्सा बनायें कि सबसे पहले, और सबसे बाद में भी, हम भारतीय हैं, फिर कुछ और।

यदि व्यवस्था सुधार नहीं सकते, तो जिले को अवैध जिला घोषित कर दें – पटेल

माही की गूंज, आलीराजपुर।

महेश पटेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में लगातार बढ़ते अवैध शराब परिवहन और उससे होने वाले सड़क हादसों पर प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन अवैध शराब की तस्करी के कारण हादसे हो रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ-साथ स्कूली बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं।पटेल ने बताया कि संविधान दिवस के दिन भी अवैध शराब ले जा रही एक गाड़ी ने बच्चों को टक्कर मार दी, जो प्रशासन की नाकामी का बड़ा उदाहरण है।अगर प्रशासन रोक नहीं पा रहा, तो जिले को अवैध जिला घोषित कर दो।

महेश पटेल ने तीखा बयान देते हुए कहा कि, जब शासन-प्रशासन अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल है, तो मुख्यमंत्री को जिले को अवैध जिला घोषित कर देना चाहिए। हर दिन हादसे, हर दिन तस्करी कृ यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

हॉस्टल और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर गंभीर आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटेल ने आदिवासी छात्रावासों और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि:हॉस्टलों की लाचार व्यवस्था के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं,कई बच्चों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन सहायक आयुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों का शोषण किया जा रहा है कृकभी रैली निकालवा रहे हैं, कभी किसी यात्रा में शामिल करा रहे हैं3 पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है।

कड़ी चेतावनीः इंदौर कमिश्नर का घेराव, फिर विधानसभा में धरना

महेश पटेल ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर सहायक आयुक्त पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं हज़ारों विद्यार्थियों और पालकों के साथ इंदौर कमिश्नर कार्यालय का घेराव करूंगा। वहाँ भी नहीं सुना गया तो विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में धरना देंगे।

हॉस्टल में वार्डन नदारद, बच्चों की तबीयत बिगड़ी

माही की गूंज, जोबट।

जोबट ब्लॉक के ग्राम जाली के बॉयज़ हॉस्टल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। वार्डन के लगातार नदारद रहने से बच्चों की देखरेख और हॉस्टल की व्यवस्थाएँ प्रभावित हो रही थीं। ग्राम जगदी मैं संचालित हो रहा बालक छात्रावास चोहली के नाम से 50 सीटर बालक छात्रावास कक्षा 1 से लेकर पांचवी तक हॉस्टल अधीक्षक पार सिंह भंवर पद पर पदस्थ है जो ड्यूटी समय पर उपलब्ध नही थे। बुधवार को जब कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तो खाना बनाने वाली महिला ही बच्चों को लेकर जोबट अस्पताल पहुँची। जैसे ही यह मामला विधायक के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत जोबट एसडीएम से बात कर पूरी घटना से अवगत कराया तथा तत्काल जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिला क्लबफुट–फ्री घोषित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल आलीराजपुर जिले ने स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य स्तर द्वारा क्लबफुट-फ्री जिला घोषित किया है। जिले में जन्मजात पैर विकृति (क्लबफुट) के सभी 0-2 वर्ष तक जन्मे सभी बच्चो का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक घोषणा की एवं आगामी जन्म लेने वाले क्लब फुट रोग से ग्रसित बच्चो का निरंतर जिला अस्पताल आलीराजपुर में उपचार किया जायेगा।

क्लबफुट एक ऐसी जन्मजात स्थिति है जिसमें नवजात शिशु के पैर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। समय पर उपचार न मिलने पर यह बच्चों में स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। आलीराजपुर में इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग की जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक श्रीमती आरती तिवारी एवं उनकी मोबाइल हेल्थ टीम की सतत प्रसव केंद्रों पर नवजात शिशुओं की निगरानी , आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं एवं सहयोगी संस्था अनुष्का फाउंडेशन ने समन्वय कर जिले के प्रत्येक प्रभावित बच्चे को चिह्नित किया और पोसती विधि के माध्यम से उनका उपचार किया। सभी एक्टिव मामलों की पहचान और समय पर कास्टिंग ,आवश्यकतानुसार टेनोटोमी प्रक्रिया ,छोटे बच्चों में पैर की स्थिति को सुधारने हेतु विशेष प्रकार के ब्रेसेस का उपयोग जो अनुष्का फाउंडेशन द्वारा निशुल्क प्रदान कर हर बच्चे की सतत निगरानी (फॉलो-अप) समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान और घर-घर संपर्क कर किया गया।

जिला कलेक्टर श्रीमति नीतू माथुर के सुचारू निर्देशन में यह उपलब्धि प्राप्त की गई जो कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को दर्शाती है। हमारे सामूहिक प्रयासों से बच्चों को भविष्य में होने वाली विकलांगता से बचाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र सुनहरे ने बताया कि समय पर किए गए हस्तक्षेप और लगातार फॉलो-अप से यह परिणाम संभव हो पाया। उन्होंने आर.बी.इस.के. जिला प्रबंधक,आर.बी.इस.के चिकित्सको ,स्वास्थ्य टीम, आशा वर्कर्स और समुदाय का आभार जताया।

समुदाय में खुशी की लहर

इस घोषणा के बाद प्रभावित परिवारों में विशेष उत्साह देखा गया। कई माता-पिता ने कहा कि पहले वे इस बीमारी से अनजान थे, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों की मार्गदर्शन से उनके बच्चों का जीवन बदल गया।

मनुष्य ने हमेशा प्रकृति का उपभोग किया पर लौटाया कुछ नही : जोशी

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में अ.भा.सद्भावना व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए पर्यावरणविद् पद्मभूषण अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि, प्रकृति के प्रचंड संकेत न समझे तो विनाश की ओर बढना तय है। मनुष्य ने हमेशा प्रकृति का उपभोग किया पर लौटाया कुछ नहीं। प्रकृति जिस वेग से बदली है, हमने उसे उतनी गंभीरता से कभी लिया ही नहीं। आज प्रचंड गर्मी का जो असहनीय वातावरण हमारे सामने है, वह चेतावनी नहीं, बल्कि दंड के रूप में खड़ा है।

जोशी ने कहाकि कभी वर्षा ऋतु के गीत गाए जाते थे, उसकी प्रतीक्षा उत्सव की तरह होती थी। अब वही वर्षा विनाश लेकर लौट रही है। फसलें सूख रही हैं, धरती तप रही है और चक्रवातों की खबरों से अखबार रोज भय से भर रहे हैं। यह प्रकृति का दंड है, जिसे हम सब भोगने को विवश हैं। प्रकृति के इन प्रचंड संकेतों को न समझे तो विनाश की ओर बढना तय है।

समापन दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में ऑनलाइन संबोधित करते हुए आपने कहाकि हमने प्रकृति को नहीं, अपनी इच्छाओं और सुविधाओं को संरक्षित किया। जिन्हें अपना कहा, उन्हें पाला-पोसा, जिन्हें अपना न माना, उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। हमने अपनी खुशी के लिए कुत्तों को घरेलू बनाया और परिणाम यह कि आज हजारों आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं। दूसरी ओर भेड़िए, चिंपांजी और वे सभी जीव, जिनकी उपस्थिति प्रकृति के संतुलन के लिए अनिवार्य है, उनकी संख्या निरंतर घट रही है। यह स्पष्ट है कि हमने अपने स्वार्थ के जीवों को तो पनपने दिया, प्रकृति के लिए आवश्यक जीवन को नहीं।

हमने पृथ्वी से सिर्फ लिया जबकि पृथ्वी को ऐसे जीव चाहिए जो लेने के साथ उसे कुछ लौटाएं भी। मनुष्य ने हमेशा उपभोग किया पर लौटाया कुछ नहीं,। आज ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो-हर संकट के केंद्र में मनुष्य की अतिशय सुविधाएं ही हैं। हम स्वयं को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति पर नियंत्रण का जो भ्रम हमने पाल रखा है, वह अब टूटने लगा है। जंगलों, नदियों और असंख्य प्राणियों का विनाश कर मनुष्य आज स्वयं को समाप्त करने के मार्ग पर बढ़ चला है। युद्ध की विभीषिका पूरे विश्व पर मंडरा रही है,मानो मनुष्य अब मनुष्य का ही शत्रु हो गया हो। यह मानकर चलिए यदि मनुष्य अपनी राह नहीं बदलेगा, तो प्रकृति उसे नहीं छोड़ेगी।

जोशी ने कहाकि पृथ्वी के इतिहास में दो बार संपूर्ण विनाश हुआ है। हर बार प्रकृति ने स्वयं को पुनर्गठित किया और ऐसे जीवन को जन्म दिया जो उसके अनुरूप हो सके। उसी क्रम में मनुष्य का उद्भव हुआ। आज मनुष्य ही उस प्रकृति को समाप्त करने की तैयारी में है,जिसने उसे जन्म दिया। अब भी समय है यदि हम स्वयं को बदलें, तभी प्रकृति हमें बचाने का निर्णय लेगी। वरना आप नहीं बदलेंगे, तो प्रकृति आपको बदल देगी।

अध्यक्षता नृत्याचार्य पद्मश्री जयराम ने की। दीप प्रज्वलन माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरीश व्यास, मुकेश ठाकुर, सोनू गहलोत, हर्षा वाघे, अमृता कुलश्रेष्ठ ने किया। अतिथि स्वागत युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ, महेश ज्ञानी, शशि भूषण ने किया। पुष्पेंद्र शर्मा, यूएस छाबड़ा, डॉ. प्रेमप्रकाश अग्निहोत्री, अजय मेहता, पं. उमाशंकर भट्ट, राजेंद्र तिवारी, प्रशांत शर्मा, राजेंद्र तिवारी, पुष्पेंद्र शर्मा, डॉ. एसएन शर्मा, कृष्ण जोशी, श्वेता पंडया, प्रफुल्ल शुक्ला उपस्थित थे। संचालन श्रेया शुक्ला ने किया।

टी एल बैठक का हुआ आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टी एल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा आगामी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रिव्यू मीटिंग संबंधी पालन प्रतिवेदन के बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही जिले में संचालित एस.आईं.आर कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा सीएमएचओ और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी बीएलओ एवं निर्वाचन में जुड़े अमले का स्वास्थ्य परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को सख्त निर्देश दिए कि ई केवाईसी की अनिवार्य रूप से प्रगति की जाए ताकि हितग्राहियों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित हो।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर मनोज गरवाल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला सहित समस्त विभाग के अधिकारियों के साथ ही सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वी.सी के माध्यम से वर्चुअल रूप से जुड़े।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमन जागरूकता अभियान अंतर्गत कार्यक्रम हुआ आयोजित

माही की गूंज, धार।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुभाष जैन के निर्देशानुसार संचालित हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमन जागरूकता अभियान अंतर्गत मंगलवार को धार तहसील के ग्राम अनारद में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिससें उनके साथ किसी भी तरीक़े की हिंसा अथवा प्रताड़ना होती है, तो उन्हें क्या क़दम उठाना चाहिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। महिलाओं को समझाया गया कि अन्याय करना और सहन करना दोनों ही क़ानूनन रूप से अपराध है। कोई भी हिंसा यदि उनके अथवा किसी अन्य महिला के साथ घटित होती है तो योजनाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने वाले स्थान जैसे महिला हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क, महिला थाना, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंसा होने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही करते है। बताया गया कि विधिक सहायता प्राधिकरण जो कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर कोर्ट केस लगवाते है जो निशुल्क होते है। किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु वन स्टॉप सेंटर जो एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, आश्रय सहायता, आपात्कालीन सहायता, परामर्श सहायता, स्वास्थ्य सेवा, क़ानूनी सहायता प्रदान करता है की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही कामकाजी महिलाओं हेतु बनाए जा रहे सखी निवास की भी जानकारी दी गई।

अलग-अलग स्थानों पर मनाया गया संविधान दिवस

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन में जिले के अलग अलग शासकीय कार्यालयों में बुधवार को संविधान दिवस मनाया गया।इस अवसर पर टाउन हॉल चंद्र शेखर आजाद नगर, जनपद पंचायत सोड़वा,जिला जेल आलीराजपुर, पीएम श्री शासकीय विद्यालय कट्ठीवाडा, शहीद क्रांतिकारी छीतू किराड़ महाविद्यालय आलीराजपुर सहित अलग अलग शासकीय संस्थानों, विद्यालयों में सामूहिक रूप से संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों, शिक्षक, विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी की तथा संविधान के मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों को स्मरण किया।

कलेक्ट्रेट में में हुआ सामूहिक उद्देशिका का वाचन

भारत सरकार द्वारा 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने के निर्णय के तहत आज कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने सभाकक्ष में उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। आज देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार व कर्तव्य हैं वे संविधान की ही देन हैं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के बिना मौलिक अधिकारों की कल्पना भी संभव नहीं थी। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सभी निर्माताओं को नमन किया।

इसके उपरांत कलेक्टर श्रीमती माथुर की अध्यक्षता में सभी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया। इसके पश्चात सभाकक्ष में संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।

कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

आखिर दो मौत का जिम्मेदार कौन, सिस्टम की लापरवाही या हम खुद...?

मामला : कुत्ते के काटने से मासूम और जहरीली ताड़ी पीने से युवक की मौत का

माही की गूंज, करवड़/पेटलावद।
अरुण पाटीदार

बीते तीन दिनों में करवड़ में हुई दो मौतों ने सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। दो अलग-अलग मामलों में ग्राम में पिछले तीन दिनों में दो मौत हो गई जो सामान्य नहीं है। इन दो मौतों में एक 9 वर्षीय मासूम की मौत कुत्ते के काटने तो दूसरे की मौत बनावटी जहरीली ताड़ी जो कि ग्राम के अलग-अलग हिस्सों में बिक रही है। एक मासूम की मौत केवल लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ले ली तो दूसरी जान, कमजोर कानून व्यवस्था ने लेली। समय पर कार्रवाई के अभाव में मौत का सिलसिला जारी रहता है। और जब ऐसी मौत होती है तो प्रशासन कुछ समय जागता है फिर वहीं स्थिति बन जाती है जो आम लोगों की मौत से खेलती है।

जहरीली ताड़ी का शिकार मृतक प्रेम पिता मन्ना मालिवाड।

जहरीली ताड़ी से तबियत बिगड़ने के बाद उपचारत मुकेश मालीवाड।

कुत्ते के काटने से मृत मासूम अरविन्द।

कुत्ते के काटने से बालक की हुई मौत, घटिया स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल

ग्राम करवड़ का 9 वर्षीय मासूम 31 अक्टूबर को अपने घर के बाहर खेल रहा था तब वह डॉग बाइट का शिकार हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए करवड़, पेटलावद, उज्जैन सहित कई जगह भटके। लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे रतलाम के मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहा 6 दिनों भर्ती रहने के बाद 23 नवंबर की शाम को मासुम ने दम तोड़ दिया। ग्राम करवड़ के गामड़ मोहल्ले में अरविंद खेल रहा था तब वह डॉग बाइट का शिकार हो गया। परिजन तत्काल उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए वहां रेबीज का वैक्सीन नहीं मिलने के चलते पेटलावद सिविल अस्पताल लाया गया था। इस बीच परिजन उसकी तबीयत में सुधार के लिए उज्जैन तक गए।

दादाजी गोपाल कटारा ने बताया कि, पिछले 6 दिनों से रतलाम मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा था वहा भी डाक्टरों द्वारा तमाम प्रयास किए गए।

राजू कटारा के पड़ोसी लूणचंद गामड़ ने बताया कि, इस बच्चे को इलाज के लिए परिजन खूब भटके। वही ग्राम के सरपंच विकास गामड़ ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी बताया। गामड़ ने बताया कि, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई सुविधा नहीं है। दयनीय हालत है, जिम्मेदार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है।

जहरीली ताड़ी ने ली जान, एक गंभीर

पेटलावद क्षेत्र अंतर्गत रुणजी पंचायत के जांबूपाड़ा गांव में मातम पसर गया है। घर में चल रहे एक शुभ अवसर की खुशियाँ गम में बदल गईं। बताया जा रहा है कि, ग्राम करवड़ से खरीदी गई ताड़ी पीने से काका-भतीजे की तबियत बिगड़ गई। दोनों को गंभीर हालत में उपचार हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां काका-भतीजे में से काका की मौत हो गई है। जबकि भतीजे का उपचार सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांबूपाड़ा निवासी प्रेम मन्ना मालीवाड़ और उनके भतीजे मुकेश पिता दिनेश मालीवाड़ के घर में 'मान' का कार्यक्रम चल रहा था। खुशियों का यह माहौल तब बिगड़ गया जब दोनों ने करवड़ बाजार से खरीदी हुई ताड़ी पी। ताड़ी पीने के कुछ देर बाद ही दोनों बेहोशी की हालत में सो गए। जब थोड़ी देर बाद भतीजे मुकेश को बेचैनी महसूस हुई, तो उसने अपने काका प्रेम को उठाने का प्रयास किया। सोए हुए काका में कोई हलचल नहीं देखी, जिसके बाद घबराए हुए भतीजे ने तुरंत परिजनों को बुलाया। परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को लेकर पेटलावद सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रेम मन्ना मालीवाड़ (काका) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मुकेश पिता दिनेश मालीवाड़ (भतीजा) को उपचार के लिए भर्ती किया गया।

बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, मुकेश पिता दिनेश का उपचार किया जा रहा है और वह निगरानी में हैं। मृतक प्रेम मालीवाड़ का पोस्टमार्टम (पीएम) किया गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच में जुटी है।

स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार लापरवाही उजागर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़ पर स्वास्थ्य सेवाओं और यहां पदस्थ डॉक्टर को लेकर कई शिकायते हो चुकी है। माही की गूंज सहित मीडिया में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था की खबरे प्रकाशित हुई। लेकिन जिम्मेदार नहीं जागे और आज भी व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। वहीं अवैध शराब ओर नशे के दूसरे साधन ताड़ी, ड्रग्स, गांजा आसानी से नशेड़ियों को उपलब्ध हो रहा है। मीडिया में लगातार खबरे प्रकाशित हो रही है लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल पुलिस ओर आबकारी केश बनाकर अपने रिकॉड दुरुस्त कर कार्रवाई खत्म कर देती हैं। जहरीली ताड़ी हो या शराब या फिर कोई दूसरा नशा इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती न ही इन पर कोई रोक लगती। ऐसे मामलों में पकड़े गए आरोपियों से जानकारी जुटा कर उनकी जड़ों तक भी नहीं पहुंचा जाता है। जिससे अवैध कारोबार बंद होने की बजाए ओर फलते फूलते है।

हर संघ संगठन और सरकारी विभाग को क्यों लेना पड़ता है विद्यार्थियों का सहारा...?

विरोध प्रद्रर्शन मे भीड़ बढ़ानी हो या सरकारी विभागो को जनजागृति लानी हो, सभी दूर स्कूली छात्रों का होता है शोषण

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो स्कूली छात्रों के कई अधिकार है, जिनमें शिक्षा का अधिकार, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में पढ़ने का अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल हैं। छात्रों को बिना किसी भेदभाव के, अपनी पहचान को बनाए रखने और अपनी बात कहने का अधिकार है, और उन्हें धमकाने या उत्पीड़न से बचाने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।

मगर इन सबसे इतर जिले में शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थियों की एक अलग ही कहानी है। जिससे जानने और समझने की वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके उलट स्कूली छात्र हमेशा किसी न किसी तरह से उत्पीड़न का शिकार होते रहते है। छात्र संठगनों के विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में इनकी उपस्थिति को इनकी मर्जी के बगैर अनिवार्य बनाया जाता है। तो सरकारी विभागों में जनजागृति के लिए भी इनका निःसंकोच इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे इसमें विद्यार्थियों की सहमति हो या ना हो।

कई विद्यार्थी संगठन अपने किसी तरह के विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन में स्कूली छात्रों को इस्तेमाल करते नजर आते है। इसके लिए वे कभी किसी स्कूल प्रींसीपल या प्रबंधन बोर्ड की परमीशन नहीं लेते। वे विद्यालय में अपने द्वारा नियुक्त संगठन के छात्रों को इसके लिए प्रेरित करते और वे छात्र पूरे विद्यालय के छात्रों को प्रदर्शन या धरने में शामिल होने के लिए उकसाते है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी सरकारी विभाग को विद्यार्थियों का इस्तेमाल करना हो तो वे विद्यार्थियों की मंशा के बगैर ही सिर्फ प्रिंसीपल या प्रबंधन समिति को सीधे आदेश दे देते और फिर प्रबंधन सीमिति या प्राचार्य, विद्यार्थियों की अनुशंसा के बगैर ही उन्हे सरकारी आयोजनों या जनजागृति कार्यक्रमों में भेड़ बकरियों की तरह घेर देते है।

इस स्थिति में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, स्कूली विद्यार्थियों के लिए बना कानून किस तरह से धड़े लगा दिया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी इसका विरोध कर भी दे तो उसकी आवाज या तो स्कूल प्रबंधन दबा देता है या फिर विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारी उसे उसकी मर्जी के बगैर आयोजनों में शामिल होने का दबाव बना ही लेते है।

यह माना कि, विद्यार्थी इस देश की मजबूत आवाज है, मगर यह आवाज कभी-कभी उनकी अपनी होती ही नहीं या तो सरकारी विभागों की या फिर छात्र संगठनों की आवाज होती है। जो दोनों ही तरफ स्वार्थ सिद्धी ही साबित होती है, इनसे असल में स्कूली छात्रों का कोई लेना -देना होता ही नहीं है। वह तो महज भीड़ का हिस्सा होकर रह जाते है।

पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। यह आयोजन पिछले सोमवार को हुआ भी, जिस तरह से इस धरना प्रदर्शन आयोजन के लिए तैयारियां बताई जा रही थी वह बहुत ही विशाल प्रदर्शन था। ऐसा लग रहा था कि, जिले भर से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन सोमवार दोपहर तक जिस जगह इकट्ठा होना था वहां महज संगठन के 150-200 छात्र ही इकट्ठा हो सके। शहर के राजगढ़ नाका से रैली निकाली गई और कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंच कर बहुत हंगामा किया गया। अपनी मांगों को लेकर परिषद के छात्र कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। कलेक्ट्रोरेट परिसर में मौजूद अधिकारियों से भी हुज्जत हुई और आखिर में अभाविप के पदाधिकारियों ने अपना ज्ञापन परिसर में लगे बेरिकेट पर चस्पा कर दिया और वहां से रवाना हो गए।

बताने वाले बताते है कि, अभाविप का यह प्रदर्शन फीका पड़ गया। कारण प्रदर्शन में अपर्याप्त विद्यार्थीयों की संख्या को बताया जा रहा है। इसके अगले दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने शहर के रातीतलाई हाई सेकेंडरी स्कूल पर हंगामा किया। इसकी खबर लगते ही स्कूल प्रबंधन ने मेन गेट पर ताले लगवा दिए और पुलिस को सूचना दी। भारी पुलिस बल स्कूल के गेट पर तैनात कर दिया गया। इसके बाद अभाविप के पदाधिकारियों और स्कूल प्राचार्य में गरमा-गरम बहस हुई। आरोप-प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। इसके बाद प्राचार्य ने नेहले पर देहला फैंकते हुए अपने उच्चाधिकारियों को प्राचार्य पद से मुक्त करने के लिए पत्र लिख डाला। जिससे अभाविप के पदाधिकारी सख्ते में आ गए।

लंबे ड्रामें के बाद प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में बताया कि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कल हुए प्रदर्शन में उन्होने अपनी स्कूल के छात्रों को जाने की परमीशन नहीं दी। इसलिए अभाविप के पदाधिकारियों ने इतना बड़ा ड्रामा किया।

अब सवाल यह कि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपने विरोध और धरना प्रदर्शन में आखिर इन स्कूली छात्रों की क्या आवश्यकता थी...? आखिर उन्हे इस प्रदर्शन में क्यों शामिल करना जरूरी था...? माना कि बात विद्यार्थी के हित की थी, तो क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी बिना स्कूली बच्चों को इसमें उलझाए उनकी समस्या का समाधान नहीं करवा सकते थे...? आखिर विद्यार्थी संगठन होता किस लिए है...? अधिकारियों से तालमेल बैठाकर समस्याओं का समाधान करवाने के लिए या फिर स्कूली छात्रों को अपने साथ प्रदर्शन में शामिल कर हंगामा करवाने के लिए...?

ऐसे ही कुछ सवाल शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन व प्राचार्य से भी है। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रदर्शन में जाने के लिए स्कूली छात्रों को क्यों रोका गया...? क्या यही कदम प्राचार्य किसी शासकीय विभाग के आने वाले बुलावे पर विद्यार्थियों को ना भेजकर उठाता...? क्योंकि कई शासकीय कार्यक्रम ऐसे होते है जहां विद्यार्थियों को उनकी मर्जी के बगैर भी जबरदस्ती भेजा जाता है। जब कोई विभाग जनजागृति के नाम पर या रैली के नाम पर इन विद्यार्थियों को अपने कार्यक्रम में शामिल करता है। क्या तब भी प्राचार्य का रवैया यही रहता है...? यहां स्वतः ही उत्तर समाने आ जाता है कि, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि वह तो शासकीय आयोजन है। मगर क्या इसमें विद्यार्थियों की मंशा कभी जानी गई?

क्योंकि, बात विद्यार्थियों के अधिकारों की है तो यहां यह बताना भी जरूरी है कि, सरकारी विभाग भी विद्यार्थियों का किस तरह से शोषण करते है। पिछले दिनों शहर की एक प्रायवेट शिक्षण संस्था में यातायात पुलिस द्वारा एक आयोजन किया गया। बच्चों को यातायात संबंधी जानकारी दी गई। इसके बाद उक्त विद्यालय ने अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को सड़कों पर उतार दिया और आने-जाने वाले लोगों में यातायात नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इन स्कूली बच्चों ने शहर के चौराहे-चौराहे पर यातायात जवान की तरह लोगों को समझाईश दी। पुलिस विभाग ने इस कार्य की सराहना भी की। खुद पुलिस अधीक्षक इस तरह के आयोजन में शामिल हुए। संस्था संचालक ने अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए विद्यार्थियों का किस तरह उपयोग किया इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मगर क्या स्कूल और इस अभियान से जुड़े बच्चों की इसमें स्वतः रूची रही होगी...? या फिर संस्था संचालकों ने बच्चों को इस काम के लिए मोटिवेट किया ताकि वे अपनी व संस्था की वाहवाही लूट सके...? इसमें विडम्बना यह कि, जिस काम के लिए पुलिस विभाग ने एक उप विभाग अलग से बना रखा हो, उसी काम की जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कहां तक उचित है...? होना तो यह चाहिए था कि, पुलिस व यातायात महकमें के अधिकारी स्कूली बच्चों को इस तरह के अभियान से रोककर पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।

इस तरह के घटना क्रम हमें यह सवाल करने पर मजबूर करते है कि, आखिर हर विरोध, धरना प्रदर्शन और शासकीय, अर्द्धशासकीय आयोजनों, निजी आयोजनों या संस्था के स्वार्थ सिद्धी आयोजनों में आखिर विद्यार्थियों का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है...?

इन स्थितियों में भी अगर हम स्कूली छात्रों के अधिकार की बात करें तो यह सरासर बेमानी ही होगी। क्योंकि वर्तमान समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आने वाले महीनों में परीक्षाएं दस्तक दे रही है। खासकर बोर्ड परीक्षाएं। हर विद्यार्थी पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ है, सफल होने के लिए विद्यार्थी घंटो-घंटो मेहनत कर रहे है। तब इस स्थिति में इस तरह के आयोजनों का क्या मतलब है...? क्या यह विद्यार्थियों की पढ़ाई और समय की बर्बादी नहीं है...? या फिर यह मान लिया जाए कि, शिक्षा का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एक कागजी पुलिंदा है...?

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422